● वर्ष-3
● अंक-22
रायपुर, रविवार
03 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 3 सितंबर रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 5 सितंबर मंगलवार को प्रकाशित होगा।

सरकार आने पर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे : शाह

कौशल विकास के नाम पर युवाओं को सट्टे की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है भूपेश सरकार

- भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और दिल्ली दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकते
- भ्रष्टाचारियो के खिलाफ एजेंसियां अपना काम जरूर करेंगी
- भूपेश बघेल ने कलेक्टर को भ्रष्टाचार के पैसे कलेक्ट करने वाला बनाकर रख दिया है
- शराब में 2160 करोड़ रुपए घोटाला तो सिर्फ टिप हैअसली घोटाला तो हजारों करोड़ का है
- प्रदेश भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र, शाह ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में शनिवार को आरोप पत्र जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार की सीरीज चलाने का आरोप लगाते हुए श्री शाह ने खुली चेतावनी दी है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार अभी पूरा सामने नहीं आया है, वह तो जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएगी, तब भ्रष्टाचार का पूरा आँकड़ा और सच सामने आएगा। श्री शाह ने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 9 वर्षों %सेवा-सुशासन-गरीब कल्याण% के कार्यक्रमों का ब्योरा देते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार को छोटी आबादी की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा। राजधानी के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, यह चुनाव छत्तीसगढ़ की सुनहरे भविष्य को आधारशिला रखने वाला चुनाव है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मिशन आदित्य की लॉन्चिंग की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पाँच सालों से वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार और घपलों-घोटालों की सरकार चल रही है। भाजपा ने उस सरकार के खिलाफ जनजागृति लाने के लिए भाजपा ने एक आरोप पत्र तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि श्रद्धेय अटलजी ने जिन सपनों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था, उन सपनों को साकार करने का वह कार्यकाल था। प्रदेश के पहले चुनाव के बाद डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व में छत्तीसगढ़ ने 15 साल तक विकास की अविरल यात्रा की। श्री शाह ने कहा कि सन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चथ्तीसगढ़ को विकसित करने के अनेक प्रयास हुए। लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ में बनी कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का साथ देने के बजाय छत्तीसगढ़ में लूट-खसोट, भ्रष्टाचार और घपलों-घोटालों की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के विकास पर सवालिया निशान लग गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी और डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास की ऊँचाई पर ले जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने घपले-घोटाले करके और छत्तीसगढ़ को एक परिवार का एटीएम बनाकर विकास के मार्ग से भटका दिया है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाले करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता तय करने वाली भाजपा की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ को तय करना है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर धर्मांतरण कराने वाली सरकार चाहिए या फिर आदिवासियों की संस्कृति को एक बार फिर से सुरक्षित व संवर्धित करने वाली सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ को तय करना है कि पिछड़ा वर्ग समाज के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जो योजनाएँ शुरू की हैं, उन्हें धरातल पर साकार करने वाली भाजपा की सरकार चाहिए या पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं में हजारों-करोड़ों रुपए का घपला करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ को तय करना है कि युवाओं से रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के झूठे वादे करके कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुँए की ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर महादेव एप को संरक्षण देने वाली भ्रषटाचार करने वाली सरकार चाहिए या युवाओं के सुविचारित विकास करने वाली सरकार चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए या जुँए की लत? भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और दिल्ली दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकते।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को श्रद्धेय अटलजी ने बनाया, भाजपा ने 15 वर्षों के अपने शासनकाल में सँवारा और अब छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार व कुसासन से भाजपा ही मुक्ति दिलाएगी। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार बनी, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि राशन घोटालों पर लगाम कैसे लगे? डॉ. रमन सिंह ने घर-घर राशन पहुँचाने की पद्धति को साकार किया।

जबकि भूपेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार द्वारा भेजे जाने वाले मुफ्त अनाज तक को छीनकर बेचने का काम किया। श्री शाह ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसियों के काम पर की जा रही टिप्पणियों पर कहा कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है। तो एजेंसी अपना काम जरूर करेगी। मनरेगा के कार्यदिवस 50 दिन बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पहली सरकार थी। मातृत्व अवकाश देने वाली, पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाली, नगरीय निकायों में आरक्षण देने वाली भाजपा की सरकार ही थी। शाह ने मुख्यमंत्री बघेल को याद दिलाया कि छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप और टेबलेट भाजपा सरकार दे रही थी, उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने घोटाला किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी पूरे देश के प्रति एक सामान भाव रखते है।

कांग्रेस ने कहा 1 लाख करोड़ रूपये के कमीशनखोरी के भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे भाजपाईयों का आरोप पत्र झूठा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के द्वारा लगाये गये आरोप को सिरे से खारिज करते हुये कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरा के आगे कोई चेहरा नहीं है सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के आगे कोई मुद्दा नहीं है भूपेश सरकार में प्रदेश के हर वर्ग खुशहाल हुआ है। भाजपा राजनैतिक हताशा में जो आरोप लगा रहे है उसका कोई प्रमाण नहीं है।

- भाजपा के आरोप पत्र से ही भूपेश बघेल की सफलता साफ नजर आ रही है जिस छत्तीसगढ़ की संस्कृति भाषा और तीज त्योहार को भाजपा ने 15 साल तक दबाकर रखा था। अपने आरोप पत्र में भाजपा छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने को मजबूर हुई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का यही सम्मान तो भूपेश बघेल चाहते है।
- जिन अमित शाह के ऊपर 1.45 लाख आरोप देश भर से केन्द्र सरकार पास पहुंचे है वे किस नैतिकता से कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे है?
- भाजपा का आरोप पत्र में जो कार्टून बनाया है उसी से साबित हो रहा है कि इसी झूठे आरोप पत्र को बनाने के लिये भाजपा छत्तीसगढ़ में ईडी को गली मुहल्लों में घुमवा रही है।
- ईडी आईटी को लगाकर प्रदेश के 200 से अधिक झूठी कार्यवाहियां करवाने के बावजूद भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक भी प्रमाणिक आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है ईडी के माध्यम से पटकथा जरूर तैयार कराया लेकिन वह भी सतही और काल्पनिक साबित हुई है।
- हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस अजीत पवार को 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले सहकारी घोटाले का प्रमुख आरोपी बनाया भाजपा के सहयोगी बनते ही ईडी ने चार्ज शीट से नाम हटा दिया।
- अडानी के सेल कंपनी में लगे 20 लाख करोड़ रू. किसका है इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है।
- भाजपा का आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है यह आरोप पत्र भूपेश सरकार के खिलाफ नहीं छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के खिलाफ लाया गया आरोप है। यह छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की भाजपा की साजिश है।
- इस आरोप पत्र से साबित हो गया कि भाजपा कांग्रेस सरकार का विरोध करते-करते छत्तीसगढ़ की विरोध करने लगी है।
- भाजपा का आरोप पत्र उसके 15 साल के सरकार के भ्रष्टाचार की यादे प्रतीत हो रहा कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई मुददा आरोप नहीं है तो अपने भ्रष्टाचारों की स्वीकारोक्ति को आरोप पत्र के रूप में प्रस्तुत किये है।
- भाजपा का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ के उन 24 लाख किसानों के खिलाफ आरोप है जिन्होंने अपना 107 लाख मीट्रिक टन धान 2640 रू. प्रति क्विंटल में बेचा है।
- यह आरोप पत्र राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9000 एवं 10000 रू. इनपुट सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों के खिलाफ है।

आरोप पत्र कांग्रेस सरकार के कारनामों का लेखा-जेखा : साव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का यह आरोप पत्र महज प्रदेश की भूपेश सरकार पर आरोप ही नहीं हैं अपितु प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शासनकाल के कारनामों, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी, अत्याचार का लेखा-जेखा और सच्चाई है, जिसे लेकर हम अब जनता के बीच जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के शासनकाल के कुकर्म और कलंक को आरोप पत्र के रूप में जनता के बीच रख रहे हैं। श्री साव ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग इस भूपेश सरकार से संत्रस्त है और इसीलिए अब हर कोई यह कह रहा है- अब नई सहिबो, बदल के रहिबो।%प्रदेश की भूपेश सरकार अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के परिवार की चिंता करना छोड़कर सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने, धोखा देने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार को झूठ-लबारी की सरकार बताते हुए श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह निश्चय कर लिया है कि आगामी चुनाव में कमल चुनाव चिह्न पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाएंगे।

आरोप पत्र के बिंदुओं से जन-जन को अवगत कराएंगे : डॉ. रमन

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव और गली-गली में किसानों-मजदूरों, माताओं-बहनों, युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों, हर वर्ग के लोगों के मुख से एक ही नारा गूंज रहा है- बदलबो बदलबो, ये दारी कांगरेस के भ्रष्ट भूपेश सरकार ला बदलबो। 2018 में कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में किए गए सारे वादे झूठे निकले, जनता की आँख में धूल झोंककर और झूठे वादे करके सरकार बनाकर सत्ता में आने वाले भूपेश बघेल के झूठ के पुलिंदे का हिसाब आज जनता मांगने तैयार खड़ी है। छत्तीसगढ़ में आज माफिया राज, लूट-खसोट के राज, भय और आतंक के राज जो स्थिति बनी हुई है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हम सब मिलकर इस आरोप पत्र के लोकर जनता के बीच जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार, 600 करोड़ रुपए का चावल घोटाला करने वाली सरकार, 2 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने वाली सरकार, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोयला घोटाला करने वाली सरकार अब जुँआ और सच्चे में लिप्त होकर महादेव एप के संरक्षण देने में लगी है।

प्रमुख समाचार

6 सितंबर को इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी

नईदिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 सितंबर तक इंडोनेशिया में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर देश की यात्रा करेंगे। उनकी इंडोनेशिया यात्रा 9-10 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। आगामी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह के देशों के संगठन के बीच संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के बाद पहला शिखर सम्मेलन होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आगामी शिखर सम्मेलन में भारत और अन्य आसियान सदस्यों के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। एक बयान के अनुसार, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं और भारत सहित इसके आठ संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।

जेट एयरवेज के संस्थापक ईडी की हिरासत में भेजा गया

नईदिल्ली। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक कथित मामले में विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने 11 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। केनरा बैंक द्वारा दायर एक शिकायत पर दर्ज किया गया। गोयल (74) को केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार रात मुंबई में अपने कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। ईडी का मामला केनरा बैंक की शिकायत के बाद इस साल मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जेट एयरवेज ने ऋण राशि का एक हिस्सा कमीशन के रूप में संबंधित कंपनियों को देकर बैंक से 538.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि ये लेनदेन धोखाधड़ी वाले थे। और इसमें ऋण राशि से धन का हेरफेर शामिल था।

आदित्य एल 1 सूरज के तूफानों को जानने के लिए हुआ रवाना

नईदिल्ली। इसरो का आदित्य एल 1 मिशन लॉन्च हो गया है। सूर्य से जुड़ें रहस्यों का पता लगाने के लिए इस सोलर मिशन की यात्रा शुरू हो गई है। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार को सूर्य के अध्ययन के लिए रवाना हुआ। आदित्य-एल1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य-एल1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही इसके करीब जाएगा। 'आदित्य एल1' को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर 'एल1' आदित्य एल1 सात पेलोड ले जाएगा, जिनमें से चार सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। इसरो ने कहा, इससे सौर गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। इस जटिल मिशन के बारे में इसरो ने कहा कि सूर्य सबसे निकटतम तारा है और इसलिए अन्य की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करके आकाशगंगा के साथ-साथ अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सूर्य पर कई विस्फोटक घटनाएं होती रहती हैं जिससे यह सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" समिति में अमित शाह कों मिली जगह

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इसके अन्य सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है। कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जगह दी गई है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आज़ाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इनमें एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरिश साल्वे और संजय कोठारी हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हर वर्ष देश में कहीं न कहीं चुनाव होता है। इससे विकास में बाधा आती है, अधिक खर्च भी होता है। इसी के चलते एक राष्ट्र, एक चुनाव की बात सामने आई होगी...कमेटी बनी है वो अध्ययन करेगी और रिपोर्ट जमा करेगी। ये अच्छी बात है। माना जा रहा है कि इससे लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ने की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं ताकि इन्हें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही संपन्न कराया जा सके।

चांद पर 101 मीटर चला रोवर, शुरू होगी स्लीप मोड की प्रक्रिया

चंद्रयान 3 मिशन अपनी नियोजित अन्वेषण अवधि के समापन के करीब पहुंच रहा है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक चंद्र दिवस तक फैला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अब चंद्रमा की रात नजदीक आने पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए स्लीप मोड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके दौरान तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने की उम्मीद है, ऐसा एस सोमनाथ ने घोषणा की है। सोमनाथ ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी भी काम कर रहे हैं। हम अगले एक से दो दिनों में दोनों को स्लीप मोड में रखने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चंद्र रात को सहन करने की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया कि रोवर ने लैंडर से लगभग 100 मीटर की दूरी तय की है। इसरो ने चंद्र अन्वेषण मिशन के हिस्से के रूप में प्रज्ञान रोवर द्वारा अपनाए गए पथ की एक तस्वीर साझा की। यह कुल यात्रा दूरी 101.4 मीटर दर्शाता है। इसरो चंद्रयान 3 मिशन द्वारा किए गए यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों से डेटा साझा कर रहा है।

विपक्षी एकजुटता- गांधी जयंती के बाद ही सामने आएगी जमीनी हकीकत

रशीद किदवई

विपक्षी गठबंधन इंडिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने में कामयाब रहा है। अब, सत्ताधारी दल पर भी दबाव है कि वह बाजी को पलटने के लिए कदम उठाए। इंडिया गठबंधन के सभी घटकों का एकजुट और तकरीबन 400 लोकसभा सीटों पर 'एक के सामने एक' की रणनीति पर सहमत होना महत्वपूर्ण है। 2014 और 2019 में चुनाव से पहले विपक्षी दलों में ऐसी एकजुटता के दर्शन नहीं हुए थे। दूसरी ओर, 18 जुलाई को हुई इंडिया की बैठक के वक्त एनडीए के भीतर जैसी हलचल दिखी थी, ठीक उसी तरह, इंडिया की मुंबई बैठक के दौरान भी एनडीए सरकार ने तलवार खींचने वाले अंदाज में संसद का विशेष सत्र बुला लिया है।

यह आकलन वाकई विचारणीय है कि चाहे एक-देश, एक-चुनाव का मुद्दा हो या महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल इनकम योजना हो या जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को सरकार को झकझोरने में काफी आनंद मिलता है। 'सी' वोटर के आंकड़े भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो इंडिया के 43 फीसदी के सामने एनडीए को 45 फीसदी वोट शेयर मिलने के संकेत दे रहे हैं। यह दो फीसदी का जो फर्क है, वह काफी कम है, खासकर यह देखते हुए कि 2019 में 105 लोकसभा सीटों पर भाजपा को तीन लाख या उससे भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई थी।

महिला आरक्षण विधेयक में महिला मतदाताओं को लुभाने का दम है। इससे 180 अतिरिक्त लोकसभा सीटें जुड़ने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें जातिगत समीकरणों को साधने की चुनौती को ध्यान में रखते हुए एनडीए के भीतर राजनीतिक सर्वस्वीकार्यता को पाना आसान नहीं होगा। स्मरणीय है कि 1951-52 और 1957 के चुनावों के दौरान भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सांसद निर्वाचित हुए थे।

ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में शामिल हैं, जो महिला मतदाताओं में अपनी लोकप्रियता के लिए मशहूर हैं। इसी तरह, एक-देश, एक-चुनाव का विचार देश में व्यापक आधार रखने वाले मध्य वर्ग के लिए तो प्रभावशाली लगता है, पर व्यवहार में संविधान के पांच अनुच्छेदों 83, 85, 172, 174 और 356 में महत्वपूर्ण संशोधन लाना असंभव नहीं, तो कठिन जरूर है, क्योंकि इसके लिए विपक्षी दलों समेत राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति जरूरी है। फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं दिखते। हालांकि मोदी सरकार एक-देश, एक-चुनाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक दिख रही है। उसने इसकी व्यवहार्यता की जांच की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। भारत में पूर्व राष्ट्रपतियों की एक शृंखला रही है, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात इनमें से किसी को भी कोई जिम्मेदारी या फिर किसी पैनल की अध्यक्षता नहीं दी गई है।एक साथ चुनाव आयोजित होने पर एक अनुमान के अनुसार, 28 लाख मतपत्र यूनिट और 24 लाख कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। एक-देश, एक-चुनाव की व्यवस्था लागू होने के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल पांच साल में एक बार ही होगा। अगर व्यवहारिक नजरिये से देखें, तो आम चुनावों के साथ करीब 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना होगी। वे राज्य जहां मई, 2024 से छह महीने पहले या बाद में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं।नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बंगाल, पंजाब, कर्नाटक और दिल्ली में किस तरह मध्यावधि चुनाव की स्थितियां तैयार करती है, वह तो फिलहाल समझ से परे है। लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साथ चुनाव होने से क्या वाकई मोदी और भाजपा को फायदा मिलेगा; खासकर, जब दिल्ली और ओडिशा में हुए पिछले चुनाव और 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में काफी विविधतापूर्ण वोटिंग पैटर्न दिखा था? दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन अपने विस्तार की कोशिशों में जुटा है। मुंबई में इसे पीजेंट ऐंड वर्कर्स पार्टी को साथ जोड़ने में कामयाबी मिली है।

भरतपुर में जिला पंचायत खोलने की मांग, ग्रामीणों ने प्रदर्शन के बाद चक्काजाम की दी धमकी

एमसीबी। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला बनने के बाद अक्सर भरतपुर के निवासी सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन को घेरते रहे हैं।इसी कड़ी में भरतपुर के निवासियों ने जिला पंचायत की मांग की है।स्थानीय निवासियों ने भरतपुर में जिला पंचायत बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।इसके लिए सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि भरतपुर में जिला पंचायत की घोषणा नहीं होती तो ग्रामवासी विरोध-प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम करेंगे।

आपको बता दें कि भरतपुर के सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम होना है। इससे पहले ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। जिसमें लिखा है कि भरतपुर तहसील और भरतपुर को जिले का दर्जा तो दे दिया गया।लेकिन जिले के नाम से कोई जिला कार्यालय विकासखंड भरतपुर में नहीं दिया गया।जबकि कलेक्ट्रेट मनेंद्रगढ़ और जिला चिकित्सालय चिरमिरी को मिला है। भरतपुर जिले से जिला अस्पताल की दूरी

करीब 150 किमी है। इस वजह से जनकपुर हॉस्पिटल से ज्यादा से ज्यादा केस में मध्यप्रदेश के शहडोल रेफर होते हैं। जिसकी दूरी करीब 100 किमी है।

सरपंच रामदेव सिंह परस्ते ने कहा यदि जिला पंचायत बनाने की घोषणा नहीं की जाती है तो ग्रामवासी और सभी सरपंच सांकेतिक चक्काजाम करेंगे।सीएम के कार्यक्रम में घोषणा नहीं होने पर आगे फिर चक्काजाम किया जाएगा।

ग्रामीण केपी सिंह ने कहा नवीन जिले का नाम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर किया गया है। मनेंद्रगढ़ में कलेक्टर कार्यालय और चिरमिरी में जिला अस्पताल की घोषणा हुई है। लेकिन भरतपुर विकासखंड में अभी तक कोई कार्यालय की घोषणा नहीं हुई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नया जिला तो बना दिया गया।लेकिन जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उसके लिए अब भी 100 से 150 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होता है।क्योंकि सारे सरकारी दफ्तर जिला मुख्यालय में हैं।अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उन्हें जिला पंचायत कार्यालय , रोजगार कार्यालय , आरटीओ कार्यालय की सुविधा मिले।यदि ऐसा नहीं होता है तो भरतपुर का नाम जिले से हटा दिया जाए।

सरपंच बृजभूषण ने कहा मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी के लोग आए और देखे कि ये कितना दूर है और यह कार्यालय की कितनी आवश्यकता है। यहां जिला पंचायत , रोजगार कार्यालय और आरटीओ कार्यालय खोल जाए।

वहीं मौके पर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाकर आंदोलन खत्म करवाया। तहसीलदार ने कहा ग्रामीणों ने जिला पंचायत की मांग को लेकर चक्काजाम किया था। मांगों का ज्ञापन लिया गया है। आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया है।

भरतपुर में जिला पंचायत कार्यालय और आरटीओ कार्यालय, रोजगार कार्यालय बनाने की मांग की जा रही है। क्योंकि जिला मुख्यालय से दूरी काफी ज्यादा है।वहीं यदि तीनों कार्यालय भरतपुर में खुले तो यही समस्या मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी वासियों को भी होगी।इसलिए जिला प्रशासन को इस गंभीर मसले का कोई हल जल्द निकालना होगा।ताकि किसी भी क्षेत्र की जनता को सरकारी काम से जुड़ी परेशानी ना हो।

भाजपा कोर कमेटी की बैठक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

■ चुनाव प्रबंधन को लेकर, प्रभारी एवं समितियों को लेकर हुई चर्चा

धमतरी। भारतीय जनता पार्टी धमतरी विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में विगत माह के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों के विषय में चर्चा की गई, साथ ही प्रदेश के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के संबंध में विभिन्न विषयों पर प्रभारी तय करने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक मे विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। शक्ति केंद्र स्तर पर हो रहे लाभार्थी सम्मेलन की समीक्षा की गई। नवमतदाता सम्मान कार्यक्रम पर चर्चा की गई। अन्य राज्यों से प्रवास पर आने वाले नेताओं के व्यवस्थापन एवं उनके कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई, साथ ही साथ घोषणा पत्र पर जनता के सुझाव संग्रहित करने के कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई । कार्य मे सुविधा की दृष्टि से मंडलों को 4 सेक्टर मे विभाजित करने एवं प्रत्येक सेक्टर के लिये प्रभारी एवं सह प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया । बस्तर से आने वाली विजय संकल्प यात्रा के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गयी । चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को कार्यभार वितरण करने एवं विभिन्न समिति बनाने के विषय मे कोर ग्रुप के सदस्यों के सुझाव लिये गये । मतदाता सूची में नाम जोड़ना एवं काटने के कार्यों के संबंध में, स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर, कॉल सेंटर की स्थापना एवं उनके उपयोग को लेकर तथा बूथ स्तर तक जाकर मोबाइल एप के माध्यम से हित ग्राहियों के आयुष्मान कार्ड क्रियेशन का कार्यक्रम इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से जिला संगठन सह प्रभारी हलधर साहू , जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार , विधायक रंजना साहू, पूर्व विधायक इंदर चंद चोपड़ा , महामंत्री कविंद्र जैन, अरविंदर मुंडी, श्यामा साहू, महेंद्र पंडित, नेहरू निषाद , चेतन हिंदुजा, बीथिका विश्वास, चंद्रकला पटेल ,कैलाश सोनकर, विजय साहू , हेमंत चंद्राकर, मुरारी यदु, दमयंती साहू ,हेमंत माला ,उमेश साहू , नवीन सांखला, विनोद पांडे उपस्थित रहे।

कोयला व राखड़ से भारी वाहनों के लिए 30 तक होगी पार्किंग की व्यवस्था

कोरबा। भारी वाहनों के चलने से होने वाले प्रदूषण को लेकर परसाभाठा विकास समिति के बैनर तले परसाभाठा, रिंग रोड, रिस्दा के व्यापारियों व परसाभाठा वासियों ने आर्थिक नाकेबंदी की। इससे मार्ग में वाहनो का आवागमन अवरूद्ध हो गया और जाम लग गया। इसकी वजह से आवागमन कर रहे आम लोगों को भी काफी परेशानी करना पड़ा। जानकारी मिलते ही बाल्को प्रबंधन की उपस्थिति में बाल्को थाना में वार्ता हुई।

इस दौरान बाल्को प्रबंधन से भरत महंत एवं चंदन मिश्रा, प्रशासन से लेविन पटेल व परसाभाठा विकास समिति से विकास डालमिया, शशि चंद्रा, पवन यादव उपस्थित रहे। बैठक में प्रबंधन ने परसाभाठा रिंग रोड, बजरंग धाम रिस्दावासी की सभी मांगों पर सहमति जताते हुए लिखित में आश्वस्त किया कि सभी मांग निर्धारित समय पर पूरी कर दी जाएगी। कोयला व राखड़ परिवहन में लगे भारी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 30 सितंबर तक कर दी जाएगी। समिति ने कहा कि अगर समय अवधि में मांग पूरी नहीं की जाती है, तो परसाभाठा विकास समिति द्वारा पुन: आंदोलन किया जाएगा और इसकी सभी जिम्मेदारी बाल्को प्रबंधन की होगी। परसाभाठा विकास समिति इस जीत के लिए सभी लोगों को आभार व्यक्त किया।

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आर्थिक नाकेबंदी की सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस के अधिकारियों के साथ कुछ आंदोलनकारियों ने अभद्रता करते हुए जमकर धक्कामुक्की की। इस वजह से विवाद की स्थिति निर्मित हुई और पुलिस को भी हल्का बल का उपयोग करना पड़ा। घटना के बाद पुलिस की गाड़ी में बैठा कर कुछ आंदोलनकारियों को थाना ले गए। यहां चर्चा उपरांत सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस की ओर से इस घटना की पुष्टि नहीं की गई है, पर विकास डालमिया का कहना है कि आंदोलनकारियों के भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने माहौल बिगाड़ने यह हरकत की।

राष्ट्रीय पोषण रैली का आयोजन

धमतरी। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोथली में स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तथा अपने आसपास व विद्यालय परिसर को स्वच्छ व साफ रखने हेतु छात्र-छात्राओं ने संकल्प लिया। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को विद्यालय में समापन समारोह का आयोजन किया गया। जिसके प्रभारी शिक्षक रामशरण मिश्रा के द्वारा संस्कृत के महत्व, पुरातन इतिहास तथा आने वाले समय में किस प्रकार संस्कृत भाषा छात्र-छात्राओं के लिए उपयोगी होगा इस पर प्रकाश डाला गया ।तथा विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती एस रामटेके ने कहा कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ व विकसित मस्तिष्क होता है। हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं । इस प्रकार संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ग्राम भोथली में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया। एन एस एस कार्यक्रम अधिकारी गणेश प्रसाद साहू ने कहा कि हरी सब्जी खाना है-एनीमिया दूर भगाना है।

केंदई रेंज में हाथियों का आंतक जारी ग्रामीण को दंतैल ने किया गंभीर

कोरबा। जिले के कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में हाथियों का आंतक अब तक जारी है। यहां के कोरबी सर्किल अंतर्गत पोड़ीखुर्द व खड़पड़ी पारा में घूम रहे 30 हाथियों के दल ने जहां बीती रात उत्पात मचाते हुए कई किसानों की फसल को रौंद दियाए वहीं सिरमिना सर्किल के पाली गांव में अचानक धमके दंतैल ने एक ग्रामीण को सूड़ से उठाकर पटक दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ग्रामीण को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथियों के आतंक से क्षेत्र के ग्रामीण काफी भयभीत हैं और रतजगा भी करने को मजबूर हैं।

वन विभाग ने क्षेत्र में घूम रहे हाथियों को खदेडने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। बीती रात रेंज के कोरबी सर्किल में घूम रहे 30 हाथियों के दल ने पोड़ी खुर्द व खड़पड़ी पारा में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों का दल ग्रामीणों के खेतों में पहुंच गया और वहां लगे धान के फसल को रौंदने के साथ तहस नहस कर दिया। यहां के ग्रामीण अपने आंखों के सामने बेबस होकर अपनी मेहनत पर पानी फिरता देखे।

आज सुबह वन विभाग को जानकारी देने पर उसका अमला मौके पर पहुंचा और नुकसानी का आंकलन शुरू कर दिया है। केंदई रेंज के सिरमिना रेंज के पाली गांव में एक दंतैल ने ग्रामीण पर हमला कर घायल कर दिया है। बताया जाता है कि बुधराम सिंह पिता देवसिंह गोड़ 32 वर्ष आज सुबह अपने खेत में फसल को देखने गया था, तभी उसका सामना दंतैल से हो गया। दंतैल से बचने के लिए वह भागने की कोशिश कर रहा था तभी विशालकाय जानवर ने अपने सूड़ से उसे उठाकर पटक दिया। जिससे वह गंभीर हो गया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को उसके परिजनों ने सरकारी वाहन बुलाकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जिस पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तत्काल अस्पताल पहुंचे और घायल ग्रामीण का हालचाल जानने के साथ ही उसके परिजनों को उपचार के लिए तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध करायी।

भाजपा से देवलाल ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने से खुशियों की लहर : प्रकाश

दल्लीराजहरा। पूर्व जनपद अध्यक्ष डौंडी व हल्बा हल्बी समाज बालोद जिलाध्यक्ष प्रकाश आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने डौंडीलोहारा विधानसभा क्रमांक 60 से बालोद जिले के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है जिससे समस्त डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के वनांचल में व सभी वर्गों में जबर्दस्त खुशियों की लहर है। श्री आर्य ने कहा कि देवलाल ठाकुर को हलबा हल्बी समाज द्वारा पूरा समर्थन दिया जाएगा जिससे देवलाल ठाकुर जी प्रचंड बहुमत से विजय होंगे।

प्रकाश आर्य ने कहा कि डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र व छत्तीसगढ़ में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीतिङ्कनीति से प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश किया है जिसका लाभ हमें 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। प्रकाश आर्य ने आगे बताया की हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी देवलाल ठाकुर के समर्थन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे है। आदिवासी वनांचलों में निवास लोगों ने एक स्वर में देवलाल ठाकुर के समर्थन के लिए हामी भरी। 2018 से झूठ की नींव में बनी भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करेगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने पर उनके द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा 15 वर्षों में किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत करा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कार्य में नहीं लौटने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एफआईआर

कोरबा। कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन संघ द्वारा विगत 21 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को एस्मा एक्ट के अंतर्गत तत्काल हड़ताल समाप्त कर अपनी सेवाएं देने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं उनके कार्य क्षेत्र में अनुपस्थिति के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के कुल 337 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग संवर्ग, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इत्यादि लोग सम्मिलित हैं। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने सीएमएचओ डॉ. एस. एन. केसरी को एस्मा एक्ट लगने के बाद भी कार्य पर उपस्थित नहीं होने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

श्रवण मरकाम ने दिखाया मानवता का परिचय

नगरी। विधानसभा सिहावा भाजपा प्रत्याशी श्रवण मरकाम नें रोड में घायल हुए युवक को देखकर अपनी वाहन रोक कर नजदीकी अस्पताल में अपनी वाहन से ले जाकर उपचार कराया। धमतरी नगरी मेन रोड के ग्राम गोहाननाला में मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी जिसमें बाइक चालक को गंभीर चोट आई हुई थी। मेन रोड से गुजरते हुए श्रवण मरकाम जी ने देखा कि रोड में भीड़ लगी हुई है दुर्घटना होने के कारण। अपनी गाड़ी से उतरकर अपने निजी वाहन द्वारा दुर्घटना ग्रसित चालक को प्राथमिक उपचार हेतु दुगली उपस्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बताया जा रहा है दुर्घटना ग्रस्त चालक का नाम रतनू यादव गुरुर निवासी है। श्रवण मरकाम जी ने अस्पताल में कर्मचारियों को अच्छे से उनका उपचार करने का निर्देषित किया।

वर्षा के लिए ननकीराम करवा रहे फूलझर में महायज्ञ

कोरबा। पूर्व गृहमंत्री व वर्तमान विधायक ननकी राम कंवर ने प्रदेश की किसानों के लिए अच्छी फसल की कामना कर सुख समृद्धि व वर्षा कराने वरुण देव् की 7 दिवसीय यज्ञ फरसवानी के आश्रित ग्राम फूलझर के हसदेव नदी किनारे शिव मंदिर में 1 सितंबर से प्रारंभ किए। प्रथम दिवस के यज्ञ पूजन कार्यक्रम में रामपुर विधानसभा विधायक ननकीराम कंवर, 7 दिवसीय यज्ञ के व्यवस्थापक व भाजपा नेता झाम लाल साहू, विश्राम कंवर, लेखराम सोनवानी भाजपा अजा मोर्चा मण्डल उपाध्यक्ष, उमेश राठौर, वेदु पटेल, पंडित पुराणिक तिवारी सहित सात ब्राम्हण पंडित, लष्मी तिवारी व कृषकगण उपस्थित थे। वरुण देव की यह महायज्ञ सात दिन तक अनवरत जारी रहेगा क्षेत्र की जनता व कृषक गण सादर आमंत्रित है। तथा विधायक कंवर लोगो को पूजा में शामिल होने के लिए अपील किया है।

खामियां मिलने पर मेडिकल प्रबंधन ने थमाया नोटिस

कोरबा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा खानपान और नर्सिंग व्यवस्था से जुड़े मामले को लेकर संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रामा सेंटर का भ्रमण करने पर उपअधीक्षक को कई प्रकार की खामियां मिली थी। मरीजों और उनके परिजनों की शिकायत पर यहां का निरीक्षण करने पर पता चला कि रोटी का वितरण सहीं तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उपचार के लिए भर्ती मरीजों की चिकित्सा के मामले में अनदेखी की जा रही है। बताया गया था कि चिकित्सा करने के बजाय मरीजों को दूसरी जगह रेफर करने की बात की जा रही थी। अधिकारी ने इसे नियमों के विरूद्ध माना और नोटिस जारी कर दिया। कहा गया कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैक कार्य की वजह से 10 दिन बंद रहेगी रायपुर मेमू पैसेंजर

कोरबा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एसईसीआर ने एक बार फिर मरम्मत व उन्नयन कार्य की वजह से तीन सितंबर से 18 ट्रेन का परिचालन निरस्त कर दिया। इसमें गेवरारोड. कोरबा. रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल भी शामिल है। यात्रियों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एसईसीआर बिलासपुर जोन द्वारा विभिन्न सेक्शनों में गतिशीलता के उन्नयन, समय की पाबंदी और चल रहे विभिन्न सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों में सुधार एवं ट्रैक रखरखाव कार्य करने का निर्णय लिया है। इसकी वजह से रेल प्रबंधन ने कई गाड़ियों का परिचालन रद्द करने की घोषणा की है। लगभग 10 दिनों के लिए ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को आवागमन में एक बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रद्द की गई ट्रेन में दो गेवरारोड. कोरबा की भी ट्रेन शामिल है। सबसे ज्यादा दिक्कत गेवरारोड़ स्टेशन के यात्रियों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि गेवरारोड स्टेशन से अभी दो ट्रेन का ही परिचालन हो रहा है। उसमें भी एक बंद कर दिए जाने का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ेगा।

रत्नाबांधा में टीना शेड निर्माण का विधायक रंजना ने किया लोकार्पण

■ ग्रामीणों ने खुशी के पल में श्रीरामचरितमानस कथा का किया आयोजन

■ जनता की मांग के अनुरूप कार्य करने वाली सक्रिय विधायक

धमतरी। रत्नाबांधा ग्रामवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग धर्म स्थलीय मानस मंच के सामने टीना शेड निर्माण की स्वीकृति की मांग निरंतर ग्रामवासियों के द्वारा की जा रही थी, जिसको विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने मांग को स्वीकार कर विधायक निधि से 8 लाख की राशि जारी किया, टीना शेड निर्माण बनने के उपरांत विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के मुख्य आतिथ्य में महाराज जी श्री राजकुमार तिवारी के मंत्रोचार के साथ जनप्रतिनिधि व ग्रामवासियों की उपस्थिति में फीता काटकर लोकार्पण

कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरपंच एवं ग्रामवासियों के द्वारा विधायक का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। टीना शेड निर्माण होने पर सरपंच उपसरपंच पंच व ग्रामवासियों के द्वारा इस खुशी के मौके पर श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन किया गया, जय मां भद्रकाली बालिका मानस मंडली के द्वारा रामकथा का संगीतमय के साथ वाचन किया गया। स्वागत उद्बोधन में गांव के वरिष्ठ कीर्तन मीनपाल ले कहा कि शेड निर्माण की मांग को विधायक रंजना साहू ने सहर्ष स्वीकार कर स्वीकृति दी, सहृदय आभार, विधायक ने क्षेत्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हुए कार्य किए हैं और उसी का परिणाम है कि विधानसभा में उसे उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित कर सम्मानित किया गया। विधायक रंजना साहू ने समस्त ग्रामवासियों को शेड निर्माण की बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर, जनता का दिया आशीर्वाद ही मेरी धरोहर है, एक जनप्रतिनिधि के नाते सेवा का अवसर मुझे मिला, यह मेरा सौभाग्य है। जनपद सदस्य धनेश्वरी साहू ने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप कार्य करने वाली सबसे सक्रिय विधायक है रंजना साहू, जिन्होंने क्षेत्र में विकास को नए आयाम तक पहुंचाएं हैं। कार्यक्रम का आभार रामभागवत मीनपाल पूर्व सरपंच व टीना शेड निर्माण की स्वीकृति के लिए शंकर लाल नेताम सरपंच ने धन्यवाद ज्ञापित किए। लोकार्पण कार्यक्रम में जनपद सदस्य अवनेंद्र साहू, जोहान पाल, तेजनारायण मीनपाल, अमर नाथ साहू, जयंत सेन, गोवर्धन साहू, भरत लाल साहू, मनोज सेन, मोतीलाल कुभकार, मीना बाई साहू, दानेश्वरी सिन्हा, रामसिंग मांडवी, विनय पदमावर, भूमेश साहू, महेश नेताम, श्यामू नेताम, नारद मीनपाल, टेकेश्वर नेताम सहित ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

568 स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया बर्खास्त, 21 अगस्त से हड़ताल पर थे

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 568 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगो को लेकर 21 अगस्त से हड़ताल पर थे। दो बार जिला प्रशासन ने काम पर लौटने को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन काम पर नहीं लौटने के कारण डीएम डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, स्वास्थ्य फेडरेशन ने 21 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, एमपीडब्ल्यू, नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर की जाए, चिकित्सकों के लंबित वेतनमान, भत्ते एवं स्टाइपेंड प्रदान किये जायें। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विशेष कोरोना भत्ता प्रदान किया जाए, अस्पताल में कार्य के दौरान डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टॉफ के साथ होने वाली हिंसा पर रोक लगाने को लेकर कड़े कदम उठाए जाने जैसी मांगे शामिल हैं।

कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर प्रशासन ने दो बार काम पर लौटने नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके काम पर कर्मचारी नहीं लौटे।

कांकेर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा बेहद आवश्यक सेवा में से एक है। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जिले के बहुत से दूरस्थ अंचल है और इनमें स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ठीक नहीं इसलिए यह कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बाइडन-मोदी की द्विपक्षीय बैठक आठ सितंबर को

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। इससे जुड़ी आधिकारिक जानकारी शनिवार को व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक की। व्हाइट हाउस के मुताबिक, बाइडन गुरुवार यानी सात सितंबर से भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति आठ सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनसे मिलकर बाइडन जी20 समूह के नेतृत्व की सराहना भी करेंगे। बयान के मुताबिक, नौ और दस सितंबर को राष्ट्रपति बाइडन जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सदस्य देशों के नेता स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित अन्य अहम वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उठाए जा रहे संयुक्त कदमों पर चर्चा करेंगे। बयान में आगे कहा गया कि जी20 देशों के नेता यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का भी आकलन करेंगे।

शिवराज की घोषनाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही

भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषनाओं की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के जम आशिर्वाद यात्रा पर भी तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्राओं से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा था कि शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते, बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं।

मुझे शक है कि केंद्र सरकार पहले चुनाव करा देंगे : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की उनकी आशंका को बल दिया है। जद (यू) नेता ने मुंबई से लौटने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आपको यह समझने की जरूरत है कि यह विशेष सत्र एक संकेत है कि वे शीघ्र चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी संभावना मैं काफी समय से देख रहा हूं और आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। संसद, जिसे पिछले महीने मानसून सत्र के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, एक विशेष सत्र के लिए 18 से 22 सितंबर तक बैठक करेगी, जिसके एजेंडे को केंद्र ने सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं, विपक्ष की बैठक पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत अच्छी रही है। अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। 5 तरह के कामों के लिए कमेटी बन गई है।

टिपरा मोथा के उपचुनाव नहीं लड़ने से भाजपा को फायदा

नई दिल्ली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने आगामी चुनावों में टिपरा मोथा के भाग न लेने के फैसले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि टिपरा मोथा के आगामी उपचुनावों में भाग न लेने से इसका फायदा भाजपा को होने वाला है। वहीं सीपीआई(एम) ने इससे भाजपा विरोधी वोट के मजबूत होने का दावा किया है। टिपरा मोथा ने कहा कि वह जो विधानसभा क्षेत्रों सिपाहीजला जिले के धनपुर और बॉक्सानगर उपचुनावों में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। सीएम मणिक साहा ने कहा, टिपरा मोथा का निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भाजपा विरोधी वोटों को मजबूत करने के विपक्ष के प्रयास में शामिल नहीं हुए। इस फैसले से हमारी पार्टी को फायदा जरूर होगा। मेरा मानना है कि भाजपा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे सीएम साहा ने कहा कि जनता के बीच भाजपा को लेकर गलत धारणा पैदा हुई है।

जाति जनगणना का टीएमसी शिवसेना ने किया विरोध

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। समन्वय समिति के गठन के साथ ही एकजुट हो कर मोदी सरकार को हराने का संकल्प भी पारित हुआ। बैठक में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम भी तय की गई। हालांकि जाति जनगणना के सवाल पर गठबंधन में उपजे मतभेद के कारण इससे जुड़े राजनीतिक प्रस्ताव को आखिरी समय में वापस ले लिया गया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना—उद्धव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति सामाजिक न्याय को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य हथियार बनाने की है। इसी कड़ी में बंगलुरू में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में जातिगत जनगणना को ले कर सामूहिक संकल्प भी पारित किया गया था। इसमें विशेष रूप से जातिगत जनगणना के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया था। हालांकि मुंबई में स्थिति बदल गई।

इंडिया गठबंधन पर भाजपा अध्यक्ष का वार, बोले-

सभी को सिर्फ परिवार की चिंता, ये लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं : नड्डा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेरी माटी, मेरा देश कार्यक्रम का भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोग मुंबई आए थे, कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, ममता दीदी को भतीजे की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है, ये काहे की नेशनल पार्टी है? ये तो परिवार की पार्टियां है। उद्धव किसकी चिंता कर रहे है, महाराष्ट्र की या आदित्य की? शरद जी की पार्टी परिवार के कारण टूटी।

नड्डा ने आरोप लगाया कि इन लोगों को सिर्फ परिवार की चिंता है। ये सभी लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत है, इसलिए उन राष्ट्रभक्तों को समर्पण भाव से याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने के उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हर वार्ड में, हर गांव और हर पंचायत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें याद करना है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ही हमारे लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों साथियों के साथ सभी शहीदों के घर पर जाकर उनके माता-पिता को, भाई-बहन को याद दिलाना है कि वो अकेले किसी परिवार के नहीं हैं, उनके साथ सारा देश है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमने तय किया है कि हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अपने आप को पर्यावरण से जोड़ा जाएगा और हर घर से जाकर मिट्टी लेकर कलश में एकत्र किया जाएगा और संकल्प लेंगे कि हम अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नेशनल वार मेमोरियल के समीप एक बहुत बड़ा अमृत वाटिका बनेगी और देशभर से लाए हुए पौधों को उस अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 साल में भारत, ब्रिटेन को पछाड़कर 11वीं नंबर से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज स्टील उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आज 97 प्रतिशत मोबाइल भी भारत में बन रहे हैं।

राजस्थान में गहलोत नहीं, लूट की सरकार, दिल्ली के अपने आकाओं को खुश करने में लगे मुख्यमंत्री

जयपुर। आगामी राजस्थान चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की राज्य सरकार पर हमलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में यह अशोक गहलोत सरकार नहीं है, घर को लूटने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार करके दिल्ली के अपने आकांओं को खुश करने और उनकी जेब भरने का काम करती है। इनको राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। कांग्रेस का मतलब बताते हुए उन्होंने कहा कि लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार और कुशासन। गहलोत सरकार का मतलब है- लाल डायरी। इसलिए आने वाले चुनाव में ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना है।

नड्डा ने आगे कहा कि राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश कहलाता था, वो आज बलात्कार, अनाचार, अत्याचार के रूप में जाना जा रहा है। इसलिए अब ये राजस्थान सहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 2जी घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरह इन्होंने अनगिनत घोटाले किए। इसलिए इनको देश से कोई लेना-देना नहीं, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छुपाने और अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है- भ्रष्टाचार क्वीट इंडिया, परिवारवाद क्वीट इंडिया, तुष्टिकरण क्वीट इंडिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और इनको सशक्त बनाने का काम भी मोदी जी ने किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी ने गरीबों की चिंता की है- गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और एक किलो दाल दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान में साढ़े 4 करोड़ लोगों को यह अन्न मिल रहा है। आज साढ़े 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए हैं। आज भारत में अतिगरीबी 1 प्रतिशत से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार हाईवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज का काम तेजी से कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में जो महिलाओं का उत्पीड़न चल रहा है, मानवता शर्मशार हो रही है। महिलाओं का खुलेआम अपमान हो रहा है, लेकिन सरकार चुप है, मूकदर्शक बनी हुई है।

राहुल बोले- अडानी पर कोई जांच नहीं करा सकते प्रधानमंत्री

दो-तीन अरबपतियों के लिए काम करते हैं भाजपा और मोदी : राहुल

रायपुर। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में अदानी समूह के स्टॉक हेरफेर के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत के पीएम अडानी पर जांच नहीं कर सकते। क्योंकि जांच के बाद नुकसान अडानी को नहीं बल्कि किसी और को होगा। छत्तीसगढ़ में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि मैं साफ कहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी पर कोई जांच नहीं करा सकते। क्योंकि जांच का नतीजा सामने आया तो नुकसान अडानी का नहीं किसी और का होगा।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी जी हिंदुस्तान के दो-तीन अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो बड़े अखबारों ने लिखा था- मोदी जी के करीबी अडानी ने हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर देशों में भेजा। फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों का दाम बढ़ाया और उन पैसों से अडानी ने आपकी पूंजी खरीदी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश और तेलंगाना में आने वाली सरकारें अडानी की नहीं बल्कि गरीबों की सरकारें होंगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कर्नाटक सरकार हो, हिमाचल प्रदेश सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या जो अभी आने वाली हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना सरकार ये सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी। अडानी की सरकारें नहीं होंगी।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हर चुनाव से पहले बीजेपी एक नंबर पेश करती है। वे कहते हैं कि उन्हें 230-250 सीटें मिलेंगी। लेकिन कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया और यह जानबूझकर किया गया था। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने की दिशा में काम करती है। भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले 5 साल में 12-15 लाख लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार करेगी।

छत्तीसगढ़ देश का केंद्र है, इसे देश का लाजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए

राजीव युवा मितान सम्मेलन में को संबोधित करते हुए सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर मोहब्बत के साथ इज्जत के साथ रहना है। यह सबसे पुराना मैसेज है जिसे हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिया। कुछ साल पहले मैंने बघेल जी से एक बात कही, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो युवाओं से पूछता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। वे बोलते हैं बेरोजगारी, मैंने श्री बघेल से कहा कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल हैं। हर जिले में आप कुछ अलग सा बनाते हो। छोटे उद्यमियों को बैंक लिंकेज नहीं मिल पाता। मैंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी से कहा कि आपका फोकस इन पर होना चाहिए। इसकी मार्केटिंग हो, मुझे खुशी है कि बघेल जी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश का केंद्र है। आपको देश का लाजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड के ब्रूक को वनडे विश्व कप के लिए टीम में नहीं रखा

नईदिल्ली। इंग्लैंड के चयनकर्ताओं ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को टीम में नहीं रखा गया, लेकिन उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं

ब्रूक ने कीवी बॉलर के होश ठिकाने लगा दिए है। दो मैच में 63 गेंद खेलकर 110 रन बना चुके हैं। पहले मैच में ब्रूक ने 27 गेंद में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से नाबाद 43 रन बनाए थे। दूसरे मैच में ब्रूक ने 36 गेंद में 67 रन की बेजोड़ पारी खेली। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है। सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और मध्यक्रम के बल्लेबाज हैरी ब्रूक के अर्थशतकों के बाद गस एटकिंसन के अपने पदार्पण मैच में चार विकेट की मदद से इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 95 रन से करारी शिकस्त दी। बेयरस्टो ने 60 गेंदों पर नाबाद 86 रन बनाए जबकि ब्रूक ने 36 गेंदों पर 67 रन की तूफानी पारी खेलकर विश्वकप की टीम में जगह बनाने के लिए अपना मजबूत दावा पेश किया। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी की मदद से इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 198 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम इसके जवाब में 13.5 ओवर में 103 रन पर आउट हो गई। इस तरह से इंग्लैंड ने चार मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड ने डरहम में खेले गए पहले मैच में सात विकेट से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड के केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें से टिम सीफर्ट ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल रहे तेज गेंदबाज एटकिंसन ने 20 रन देकर चार विकेट लिए जबकि स्पिनर आदिल राशिद ने 18 रन देकर दो विकेट हासिल किए। तीसरा मैच रविवार को एजबेस्टन में खेला जाएगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सूर्य के सफर पर निकला इसरो का आदित्य एल1

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के उद्देश्य से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन 'आदित्य एल1' का यहां स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही 23.40 घंटे की उलटी गिनती समाप्त हुई, 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11.50 बजे निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। यह लगभग 63 मिनट की पीएसएलवी की सबसे लंबी उड़ान होगी। इसरो के अनुसार, 'आदित्य-एल1' सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान, 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु 'एल1' के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा।

कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा

नईदिल्ली। सरकार ने देश में उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा दिया है वहीं डीजल और एटीएफ (विमान ईंधन) के निर्यात पर उपकर बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। देश में ही उत्पादन वाले कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाने वाला कर घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जो पहले 7,100 रुपये प्रति टन था। अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 5.50 रुपये प्रति लीटर था। वहीं, विमान ईंधन पर एसएईडी दो रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर चार रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर एसएईडी शून्य बना हुआ है। अधिसूचना के अनुसार, कर की नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी कांच के इंपोर्ट पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की

नईदिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते उत्पादनों से बचाने के लिए घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चीनी कांच के आयात पर 243 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेगा। एक घरेलू कंपनी द्वारा शिकायत किए जाने पर वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन में बनने वाले या वहां से निर्यात किए गए '1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई और 0.4 वर्ग मीटर या उससे कम आकार वाले कठोर कांच' की कथित डंपिंग की जांच की है। कांच प्रसंस्करण की सुरक्षा/विशेषता के एक निकाय फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास ने डंपिंग-रोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दिया था।

विनिर्माण गतिविधियां तीन महीने के शीर्ष पर

नई दिल्ली। देश की विनिर्माण गतिविधियों में नरमी के बाद फिर रफ्तार पकड़ी है। नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि के दम पर विनिर्माण गतिविधियां अगस्त, 2023 में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पिछले महीने बढ़कर 58.6 पर पहुंच गया। यह इसका जून के बाद तीन माह का उच्च स्तर है। उस दौरान विनिर्माण पीएमआई 57.8 रहा था, जबकि जुलाई में यह 57.7 रहा। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में लगातार 26वें महीने परिचालन में सुधार हुआ है। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में एसोसिएट निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, पीएमआई के ताजा आंकड़े अगस्त में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति में मजबूत सुधार का जीवंत तस्वीर पेश कर रहे हैं।

महंगाई पर काबू पाना प्राथमिकता, करनी पड़ेगी जमाखोरों पर सख्ती

जयंतीलाल भंडारी

यकीनन महंगाई कम करना सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाकर बड़ी राहत दी है। हाल ही में रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में भी महंगाई को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता जताई गई और ब्याज दर को न बदलते हुए 6.5 प्रतिशत रखने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई पर काबू पाना सरकार की वर्तमान प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार, जून, 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 4.87 फीसदी थी, वह जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई। पिछले वर्ष जुलाई, 2022 में खुदरा महंगाई 6.71 फीसदी थी। अनाज की कीमतों में ऊंची महंगाई दर स्पष्ट देखी जा रही है और उम्मीद से कम खाद्यान्न उत्पादन का जोखिम भी है। खुदरा महंगाई दर केंद्र सरकार के छह प्रतिशत की तय ऊपरी सीमा से अधिक है।

इस समय खाद्य कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कई कारण उभरकर दिखाई दे रहे हैं। काला सागर अनाज समझौता खत्म करने के रूस के फैसले और गेहूं उपजाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में बारिश न होने के कारण अनाज के दाम बढ़ गए हैं। देश में फसलों पर सफेद मक्खी के प्रकोप और मानसूनी बारिश के असमान वितरण से भी सब्जियां महंगी हुई हैं। स्थिति यह है कि सीमित आपूर्ति के कारण देश में थोक गेहूं की कीमतें पिछले दो महीनों में तेजी से बढ़ी हैं। सरकार के गोदामों में भी गेहूं के स्टॉक में कमी आई है। इसके

अलावा, बाजार में नकदी ज्यादा रहने से भी महंगाई बढ़ी है। देश में अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून के साथ न देने से भी खाद्यान्न उत्पादन में कमी का जोखिम बढ़ा है।

बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। पिछले साल रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद गेहूं के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई गई थी, वह अब तक जारी है। प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया गया है और हाल ही में सेला चावल के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया है। सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के जरिये रियायती दर पर गेहूं और चावल, दोनों बेच रही है। इसी तरह सब्जियों, दालों और तिलहन के दाम काबू में रखने के लिए भी खास उपाय किए गए हैं। सरकार पेट्रोल का आयात खर्च घटाने और कम कीमत रखने के मद्देनजर पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग कर रही है। मगर विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी खाद्य महंगाई नियंत्रित नहीं है। वित्त मंत्रालय ने भी जुलाई, 2023 की अपनी रिपोर्ट में आगाह किया है कि आगामी महीनों में भी महंगाई की दर ऊंची बनी रह सकती है। सचमुच, इस बार महंगाई से लड़ाई सरकार और केंद्रीय बैंक के लिए कड़ी चुनौती बन गई है। महंगाई पर नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे आम आदमी की मुश्किलों के साथ आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है और इसका चुनावी असर भी पड़ता है। ऐसे में, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा महंगाई दर पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को अधिक कारगर उपायों के साथ आगे आना होगा। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करनी होगी। अतिरिक्त नकदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को ध्यान देना होगा। आवश्यक खाद्य पदार्थों का आयात करके आपूर्ति बढ़ाने से महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार के पास जमा विदेशी मुद्रा भंडार भी महंगाई नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत की पेट्रोल-डीजल की दिग्गज कंपनियां घरेलू कीमत घटाने की स्थिति में हैं। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती करने से महंगाई में व्यापक कमी आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर सीमा व उत्पाद शुल्क में और राज्य सरकारों द्वारा वैट में कमी करना जरूरी है। मंत्रालयों के बजट में कटौती से बजट घाटे को लक्ष्य से अधिक होने से बचाया जा सकता है।

अधीर रंजन चौधरी : मुश्किल हालात बनाता वफादार नेता

आदिति फडणीस

अधीर रंजन चौधरी द्वारा लोक सभा में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगे जाने के बाद सदन से उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है। चूंकि उक्त टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है इसलिए हम उन्हें दोबारा यहां नहीं लिख सकते हैं। असल बात यह है कि हम एक बार फिर लोकसभा में चौधरी की टूटीफूटी हिंदी में उनके भाषण सुन पाएंगे। बात तो यह भी है कि चौधरी को 2019 में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में कांग्रेस का नेता उनके वाक् कौशल के लिए नहीं बनाया गया था। सोनिया गांधी पश्चिम बंगाल के बेहरामपुर से सांसद चौधरी को बहुत पसंद करती हैं। वह उन्हें 'लड़ाका' कहती हैं जो कि वह हैं। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों के खिलाफ उन्होंने अथक लड़ाई लड़ी है। दोनों ही उन्हें निशाना बनाते हैं, हालांकि दोनों की शैली एकदम अलग-अलग है। बनर्जी ने बतौर मुख्यमंत्री अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके मुर्शिदाबाद और माल्दा जैसे चौधरी के प्रभाव वाले इलाकों में उनके कुछ करीबियों को आपराधिक मामलों में उलझा दिया है। कई ने इसी आशंका की वजह से तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। संसद में भाजपा उनके साथ खेलती है और गांधी परिवार द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय की बात करती है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव की बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी के भाषणों का उदाहरण देते हुए कहा था कि 'गुड़ का गोबर कैसे किया जाता है कोई इनसे सीखे।' भाजपा ने मजाक उड़ाते हुए विपक्ष के नेता को अपने कोटे का समय देने की पेशकश की ताकि वह भाषण दे सकें। अतीत में गृहमंत्री अमित शाह ने चौधरी को खुद अपने ही जाल में उलझ जाने दिया था जब अनुच्छेद 370 पर चल रही बहस में नेता प्रतिपक्ष कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर पूरी तरह राह भटक गए थे। उनके भाषण के वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि सोनिया गांधी मुड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही हैं जिसकी उन्होंने अनदेखी कर दी। ऐसा मोटे तौर पर इसलिए हुआ कि चौधरी अपनी खराब हिंदी में भी बात कहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चौधरी को राजनीति विरासत में नहीं मिली है और उन्होंने अपने बलबूते पर यह मुकाम बनाया है। वह बंगाल के ऐसे इलाके से आते हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। उनके क्षेत्र के मतदाताओं में औसतन 51 फीसदी मुस्लिम हैं। माल्दा-मुर्शिदाबाद-उत्तर दिनाजपुर क्षेत्र दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। पूर्व रेल मंत्री अब्दुल गनी खान चौधरी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अंतर केवल यह है कि अधीर रंजन चौधरी एक मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव जीतने वाले हिंदू नेता हैं। वह लगातार पांच बार से लोकसभा सदस्य हैं। यह बात लोकसभा में वरिष्ठता की सूची में उन्हें ऊपर लाती है हालांकि पार्टी में शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे अच्छे वक्ता मौजूद हैं। चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राजीव गांधी के दौर में की थी। उन्होंने अपना दूसरा चुनाव 1996 में नवग्राम विधानसभा क्षेत्र से फरारी के दौरान जीता क्योंकि वह हत्या के आरोप में वांछित थे। उनके समर्थकों ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में उनके भाषण कैसेट रिकॉर्डर के माध्यम से बजाए। बाद में वह हत्या के अन्य आरोपों में जेल भी गए। जेल में रहते हुए उन्होंने द स्टेट्समैन समाचार पत्र का सबस्क्रिप्शन लिया और बांग्ला से अंग्रेजी का शब्दकोष मंगाकर अंग्रेजी सीखी। बाद में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में भाषण दिया और संवाददाताओं के समक्ष याद किया कि उन्होंने भाषा कैसे सीखी। राजनीति में धन की आवश्यकता होती है और उन्होंने वैसे ही धन जुटाया जैसे कि उन दिनों अन्य लोग जुटाते थे यानी सरकारी ठेकेदार बनकर। उनकी राजनीति रॉबिनहुड शैली की राजनीति थी जो वाम उग्रपंथ से निकली थी। वास्तव में उसी ने उन्हें राजनीति में शामिल होने की प्रेरणा भी दी थी लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने उसे त्याग दिया।

एक देश- एक चुनाव की प्रासंगिकता

श्याम जाजू

2023-24 देश के लिए चुनावी वर्ष कहे जा सकते हैं। इस साल 2023 में दस राज्यों में चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जिनमें से 5 राज्यों में हो चुके हैं और पांच में होने वाले हैं। वहीं अगले साल 2024 में सात राज्यों के साथ लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। अर्थात दो वर्षों में 18 चुनाव! इनके साथ ही कई विधानसभाओं और लोकसभा की कुछ सीटों के लिए उप चुनाव भी होंगे। मतलब यह कि आने वाले दिनों में देश चुनावों में व्यस्त रहेगा।

पर ऐसे समय में जब देश-दुनिया अनेक चुनौतियों से दो-चार हो रही है, पूरी मानवता कोविड और यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभावों से जूझ रही है और जिस समय देश सघर्षों से लड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है, क्या ये उचित लगता है कि सारा देश और प्रशासनिक तंत्र चुनावों की व्यवस्था में ही लग जाए? क्या यह उचित नहीं होगा कि सारे चुनाव एक बार में, एक साथ कराये जाएँ और बार-बार चुनावों पर होने वाले खर्च और व्यवधान से बचा जा सके?

एक साथ चुनाव कराने का एक मुख्य तर्क यह है कि इससे काफी समय और संसाधनों की बचत होगी। वर्तमान में, भारत में चुनाव चरणों में होते हैं, जिसकी प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। यह न केवल सरकार के सामान्य कामकाज को बाधित करता है बल्कि राजकोष पर बड़ा बोझ भी डालता है। एक साथ चुनाव कराने का मतलब होगा कि प्रक्रिया की अवधि और समग्र लागत को कम करना।

एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में एक और तर्क यह है कि इससे अधिक स्थिर शासन को बढ़ावा मिलेगा। लगातार होते चुनावों और सत्ता परिवर्तन से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता बाधित होती है। साथ ही सरकार की जवाबदेही में भी कमी आ जाती है। सरकार का ध्यान शासन से हटकर चुनाव प्रचार पर चला जाता है। एक साथ चुनाव कराने का मतलब होगा कि सत्ता में रहने वाली सरकार पूरे कार्यकाल के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, जिससे अधिक बेहतर शासन की संभावना बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त, एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। जब चुनाव अलग-अलग समय पर और बार बार होते हैं, तो मतदाताओं को अरुचि होनी शुरू हो जाती है जिससे मतदान प्रतिशत कम हो जाता है। एक ही समय में सभी चुनाव कराने से, मतदाताओं के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अधिक संभावना होगी।

प्रधानमंत्री मोदी देश में समकालिक चुनावों के बड़े हिमायती है और अनेक बार देश में एक साथ चुनावों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। 2014 के चुनावों से पूर्व इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया था। उसी साल जून में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने एक साथ चुनाव कराने को अत्यंत आवश्यक बताया था और चुनाव-आयोग का आव्हान किया था कि वो यह संभव बनाने की दिशा में काम करे। प्रधानमंत्री ने एक साथ चुनावों की वकालत करते हुए कहा था कि इस कदम से सार्वजानिक जीवन में पारदर्शिता बढ़ाने व भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की पहल का समर्थन चुनाव आयोग भी कर चुका है पर वह इसके लिए सभी दलों की सहमति चाहता है। पूर्व में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी 1995 और 2010 में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया था। उन्होने कहा था, चुनाव सुधार पर सकारात्मक चर्चा का वक्त आ गया है। समय आ गया है कि हम पुराने समय में लौट जाएं, जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होते थे।

एक साथ चुनावों की कवायद, दरअसल, लम्बे समय से चल रही है। दिसंबर, 2015 में भी संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने देश में सभी विधानसभा चुनावों को दो चरणों में संपन्न कराने की संस्तुति की थी। अप्रैल, 2018 में विधि आयोग ने समकालिक चुनावों पर तीन पृष्ठों का एक श्वेत पत्र जारी किया था। इस मसौदे में विधि आयोग ने तथ्यों के आधार पर समकालिक चुनावों की जरूरत पर बल देते हुए इससे जुड़ी व्यापक चर्चा का आह्वान भी किया था। आयोग के मसौदे में समकालिक चुनावों को लेकर पूर्व में उठी मांगों अथवा सिफारिशों का हवाला भी दिया गया था। इतिहास में जाकर पड़ताल करें तो समकालिक चुनाव का विचार सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा 1983 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में आया था। इसके बाद 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट और वर्ष 2015 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी समकालिक चुनावों पर सकारात्मक चर्चा उभर कर आई थी।

इस विषय पर 2017 में नीति आयोग ने भी एक विश्लेषण पत्र जारी करके समकालिक चुनावों की सिफारिश की थी। नीति आयोग ने तो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करने का सुझाव भी दे दिया था। आयोग ने अपने वक्तव्य में कहा था, हम 2024 में लोकसभा चुनाव से एक साथ दो चरणों में चुनाव कराने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अधिकतम एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करनी होगी या कुछ को कार्यकाल विस्तार देना होगा।

दरअसल आज़ादी के बाद देश में चुनाव एक साथ ही होते थे। 1951-52 में पहले आमचुनाव में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। यह क्रम 1967 तक निर्विघ्न चला पर 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय पूर्व भंग होने और 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होने से यह क्रम टूट गया। इसके बाद से सिर्फ आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा ही अपना कार्यकाल पूर्ण कर पायी है।

अब स्थिति यह है कि देश में प्रतिवर्ष छोटे-बड़े औसतन 5-7 चुनाव होते हैं। इन लगातार होते चुनावों से न केवल बड़ा खर्च होता है बल्कि लगातार लागू होती आचार-संहिता से शासकीय कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। नीति-आयोग के अनुसार लगातार चुनाव होते रहने से नीति निर्माण में स्थायित्व नहीं रहता और मतदाताओं को लुभाने के चलते संरचनात?मक सुधारों के बजाय अदूरदर्शी और लोकलुभावन निर्णयों को ज?यादा प्राथमिकता दी जाती है।

एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में दिए जाने वाले मूलत: चार तर्क हैं =

1) इससे बार-बार चुनाव कराने के खर्च से बचा जा सकेगा जिससे न केवल धन बल्कि समय की भी बचत होगी। 2) मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचार-संहिता की वजह से शासकीय कार्यों को ठप्प होने से रोका जा सकेगा और सरकारें बार-बार चुनाव के बजाय शासन करने पर ध्यान दे पाएंगी। 3) सार्वजनिक जीवन में चुनाव से होने वाले व्यवधानों को सीमित किया जा सकेगा। 4) लगभग हर समय किसी न किसी चुनावों में तैनात हमारे सुरक्षा-बलों को सुरक्षा और क़ानून-व्यवस्था के रख-रखाव में लगाया जा सकेगा।

इन तर्कों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की एक साथ चुनावों की योजना को व्यापक जन-समर्थन हासिल है। पर अहम् सवाल यह है कि जब सबकुछ इतना माकूल है तो रुकावटें किन बिंदुओं पर हैं? दरअसल, समकालिक चुनावों की राह में रुकावट सभी दलों की सहमति के प्रश्न पर है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि वह एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है, बशर्ते सभी दलों का इस पर एकमत बन जाए। पर क्या सभी राजनीतिक दल इस पर सहमति बना पाएंगे?

बहरहाल समय आ गया है जब हम गंभीरता पूर्वक %एक राष्ट्र, एक चुनाव% की अवधारणा पर कार्य करें। बहरहाल इस दिशा में पहल करते हुए केंद्र सरकार ने %एक देश एक चुनाव% को लेकर एक समिति का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों विधानसभा चुनाव भी होंगे या नहीं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद् (भाग-13)

गतांक से आगे...

यश्च विष्णु: , यश्च महेश्वर:, यश्च पुरुष:, यश्चेश्वर:, या सरस्वती, या श्री:, या गौरी, या प्रकृति:, या विद्या, ये वेदा:, साङ्गा:, सशाखा:, सेतिहासा: ये पञ्चाग्नय:, या: सप्त महाव्याहृतय:, ये चाष्टौ लोकपाला: ये चाष्टौ वसव:, ये चैकादश रुद्रा:, ये च द्वादशादित्या:, ये चाष्टौ ग्रहा: यानि च पञ्च महाभूतानि, यश्च काल:, यश्च मनु:, यश्च मृत्यु:, यश्च यम:, यश्चान्तक:, यश्च प्राण:, यश्च सूर्य:, यश्च सोम:, यश्च विराट् पुरुष:, यश्च जी, यश्च सर्वम।

यह सुनकर प्रजापति ने कहा- मंत्रराज आनुष्टुभ मंत्र के प्रत्येक अक्षर- 32 अक्षर से एक स्तुति मंत्र प्रकट हुआ है, इन्हीं मंत्रों से स्तुति करनी चाहिए। [यहाँ प्रजापति ने नृसिंह भगवान् की स्तुति के रूप में बत्तीस मन्त्र प्रकट किये हैं। नृसिंह भगवान् को अनुष्टुप्मय कहा गया है (देखें इसी उपनिषद् के 1.2 की पाद टिप्पणी)। सृष्टि के उद्भव विकास का उन्हें आधारभूत तत्त्व स्वीकारा गया है। यहाँ उन्हीं बत्तीस घटकों को आधार मानकर नृसिंह भगवान् की स्तुति की गई है।

बत्तीस मन्त्रों का विशेष प्रयोजन अनुष्टुप् छन्द के बत्तीस वर्ण होने से है। बत्तीस वर्णों वाले अनुष्टुप् छन्द के बत्तीस मन्त्रों द्वारा अनुष्टुप्मय नृसिंह भगवान् की स्तुति किया जाना और उनकी बत्तीस शक्ति धाराओं से तादात्म्य स्थापित करके लाभान्वित होना समीचीन ही है।]

इसी से भगवान् प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए जो नित्य प्रति इन मंत्रों से स्तुति करता है, वह प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर उनके विराट् रूप को देख लेता है और अमृतत्व को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह जानने वाले को वही (उक्त फल प्राप्त होता है। यही महोपनिषद् है)। एक घार देवताओं ने श्रद्धापूर्वक प्रजापति ब्रह्माजी से प्रश्न किया कि हे भगवन! मंत्रराज आनुष्टुभ का जो महाचक्र नामक चक्र है, उसके बारे में बताने की कृपा करें। यह महाचक्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा मुक्ति दाता है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। [व्यक्त-अव्यक्त सृष्टि को अनुशासित ढंग से संचालित करने के लिए जो व्यवस्था चक्र बनाया गया है, उसे परमपुरुष का महाचक्र कहना उचित है। नृसिंह षट्चक्रोपनिषद् में चक्रों के विभिन्न रूप वर्णित हैं।]

प्रश्न सुनकर ब्रह्माजी ने कहा- छ: अक्षरों से युक्त यह सुदर्शन नामक महाचक्र है। छ: ऋतुएँ इसमें छ: अरों के समान हैं। यह अरे इसकी नाभि में प्रतिष्ठित होते हैं। मायारूप नेमि से यह सम्पूर्ण चक्र आवेष्टित है। आत्मा का स्पर्श माया नहीं करती है, इसलिए बाहर से ही वह षड्दल चक्र माया द्वारा घिरा हुआ है।

क्रमश: ...

देश को स्वराज का नारा देने वाले दादाभाई नौरोजी

निधि अविनाश

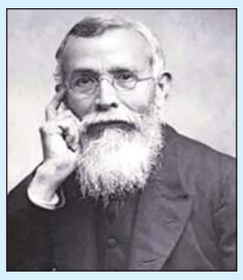

'हम अंग्रेजों से कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए'। अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान दादाभाई ने अंग्रेजों के लिए यहीं बात कहीं थी। अंग्रेजों के शासन को सबसे पहले स्वराज के जरिए चुनौती देने वाले भारत के सबसे बुजुर्ग नेता थे दिग्गज दादाभाई नौरोजी।

4 सितम्बर 1825 को मुंबई के पारसी परिवार में जन्में दादाभाई का बचपन आर्थिक संकटों में गुजरा। मां मानेकबाई पढ़ी-लिखी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद अपने बेटे दादाभाई को अच्छी शिक्षा देने का ठान लिया। मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दादा ने कुछ सालों तक गणित के अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी।

कहा जाता है कि महात्मा गांधी से पहले अगर किसी को देश का प्रमुख नेता कहा जाता था तो वो दादाभाई नौरोजी थे। जातिवाद और सम्राज्यवाद के विरोधी के तौर पर उनकी एक पहचान बनी। दादाभाई नौरोजी साल 1892 में ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे और ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। साल 1855 का एक किस्सा जिसका जिक्र हर कोई करता है। जब वह 1855 को लंदन पहुंचे तो वह वहां का नजारा देखकर हैरान हो गए थे। जब उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को सुख और समृद्धि के साथ देखा तो वह काफी दंग रह गए थे क्योंकि भारत की स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत थी। जब वह ब्रिटिश के संसद में पहुंचे तो उनका मकसद केवल भारत की गरीबी और अंग्रेजो के शासन की क्रूर निति के खिलाफ आवाज उठानी थी। उन्होनें अपना पहला चुनावी अभियान साल 1886 में होलबर्न से शुरू किया लेकिन वह कामयाब नहीं रहे। वह फिर भी हार नहीं माने और ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने पूंजीवादी की आलोचना की और मजदूरों के अधिकारों पर अपनी आवाज उठाई और नतीजा ये निकला कि लोगों को उनपर भरोसा होने लगा।

साल 1892 में उन्होंने लंदन के सेंट्रल फिंसबरी से 5 वोटों से चुनाव जीता। इस दौरान उन्हें दादाभाई नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाने लगा। एक लंबे संघर्ष के बाद दादाभाई एक सांसद के रूप में ब्रिटिश के संसद पहुंचे और भारत की आवाज बने। उन्होंने ब्रिटिश के संसद में बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन अपनी ताकत से भारतीयों को अपना गुलाम बना रहा है और भारतीयों पर कड़े जुल्म कर रहा है। दादाभाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखी। दादभाई ने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी लेकिन साथ ही भारत में कुछ ऐसे बदलाव भी किए जिसकी कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। दादाभाई ने 1840 के दशक में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। महज 5 साल के अंदर ही बॉम्बे में लड़कियों का स्कूल छात्राओं से भरा हुआ नजर आया। दादाभाई ने अपने मजबूत इरादे से देश में लैंगिक समानता की मांग की। उनका कहना था कि भारतीय एक दिन ये बात जरूर समझेंगे कि महिलआओं को दुनिया में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का उतना ही हक है जितना की देश के हर एक पुरुष को।

तीन पहिए दोनों तरफ, मगर चलेंगे किस तरफ !

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) की बैठक के साथ राज्य के नए सत्ता समीकरण के महागठबंधन ने भी अपनी बैठक बुला ली है। अब महाराष्ट्र में 28 पार्टी बनाम तीन पार्टी का मुकाबला सामने आ रहा है। हालांकि दोनों के स्तर में फर्क है। एक राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है, तो दूसरा राज्य में अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत बना रहा है। महाराष्ट्र की सीमाओं में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का छोटा भाग एक तरफ है, तो दोनों ही दलों के बड़े हिस्से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठे हैं। शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार की राकांपा के साथ अटूट कांग्रेस है, लेकिन उसकी ताकत पर अभी कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है।

राकांपा से अलग हुए नेताओं का दावा है कि पूरी पार्टी उनके साथ है, जबकि यही कुछ बात शिवसेना का शिंदे गुट कहता है। किंतु वास्तविकता के धरातल पर दोनों पालों में विधायक और सांसद अपनी-अपनी निष्ठा के साथ डटे हुए हैं। इसलिए एकतरफा राजनीति या किसी एक ओर झुकाव की संभावना कम नजर आ रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जिस तरह सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें पुराने शिवसैनिकों का विश्वास मिल रहा है, उससे उन्हें खाली हाथ नहीं माना जा सकता। उनके पास कार्यकर्ताओं की अच्छी फौज है। साथ में खड़े नेता भी निष्ठा के साथ दिखाई दे रहे हैं। यही हाल राकांपा का भी है, जिसमें शरद पवार के समर्थक उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। शक्ति प्रदर्शन के अवसरों पर वे पूरी ताकत के साथ मौजूद रहते हैं। इसीलिए राकांपा अजित पवार गुट के नेता

राकांपा प्रमुख शरद पवार को सीधी चुनौती देने से बचने लगे हैं। वे फोटो हटाने की बात हो या उम्र की चर्चा जैसे मुद्दों को उठाने से संकोच करने लगे हैं। यहां तक कि अपनी सभाओं को शक्ति प्रदर्शन ह भी पीछे हटकर उसे उत्तरदायित्व से जोड़ रहे हैं। उन्हें यह बात समझ में आ रही है कि उनके लिए बगावत शब्द उसी तरह महंगा है, जैसा शिवसेना की भाषा में %गद्दारी% शब्द को भुनाया जा रहा है, दोनों के बीच स्थितियां यह हैं कि एक के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो दूसरे के पास हासिल आई ताकत को संभालना आसान नहीं है। हालांकि यह सर्वेक्षण आमने-सामने की लड़ाई के अनुमानित परिणाम हो सकते हैं, मगर यह भी तय है कि आने वाले समय राज्य की चुनावी बिसात पर हर दल को अपने से मुकाबला करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आम तौर पर राज्य में कांग्रेस गठबंधन बनाम भगवा गठबंधन मुकाबला होता आया है। किंतु नए समीकरणों में शिवसेना विरुद्ध शिवसेना और राकांपा विरुद्ध राकांपा मुकाबले के अनेक निर्वाचन क्षेत्र तैयार हो सकते हैं। कुछ हद तक, बीत रही, जो बात...!

पिछले दिनों एक मीडिया हाउस के लोकसभा के चुनावी सर्वेक्षण में राज्य के पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ की अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई दी। नए चुनावी समीकरणों में उन्हें आधा-आधा बांटकर संतोष करना पड़ सकता है। यह संकेत विपक्ष के लिए अच्छे हैं, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य तक सब्जबाग बनाए बैठे सत्तापक्ष के लिए अच्छे नहीं हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के वर्ष 2009 के विधानसभा चुनावों में चलाए गए दांव की तरह शिवसेना और राकांपा दोनों के दोनों घटकों की तरफ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यह परेशानी केवल इन दोनों दलों तक ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने समस्या बन सकती है। अजित पवार की राकांपा के पास नेताओं की बड़ी फौज है, जो सहज समझौते के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के पास भी महत्वाकांक्षी नेता बहुत हैं, जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में यदि कोई तीसरा दल मैदान में आएगा तो सबका खेल बिगाड़ेगा। आज नए परिदृश्य में मतदाता भले ही भ्रम में हो या फिर वह निष्ठा को प्राथमिकता देता हो। अंत समय पर लिया गया निर्णय चुनाव की शक्ल को आसानी से बदल सकता है। यही वजह है कि सत्ता सुख को भोगने के बाद भी कोई आत्मविश्वास के साथ नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि उसे अपनी पार्टी की टूट को तार्किक ढंग से आम जन को समझा पाना आसान नहीं हो पा रहा है।

करीब पौने चार साल पहले जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाआघाड़ी सरकार बनी थी, तो उस समय यह तय हो चला था कि राज्य में अब मुकाबला भाजपा विरुद्ध अन्य सभी दल का होगा। उस दौरान तीन दलों की मिलकर विधानसभा में डेढ़ सौ से अधिक सीटें हो रही थीं। उनमें मतदान के लिए आवश्यक सभी समीकरण जुड़ रहे थे। तब भाजपा भी अकेली पड़ती दिख रही थी। किंतु वर्तमान में भाजपा अकेली नहीं है, लेकिन जो दल साथ हैं वे विपक्ष के पाले से ही आए हैं। उनके नेताओं की ताकत वर्तमान विपक्षी दलों से ही तैयार हुई है। इसलिए उनकी पूरी शक्ति भाजपा को मिलना संभव नहीं। यहीं पर चिंताओं का बाजार गर्म होता है। यहीं से चुनाव आसान नजर नहीं आते हैं।

वर्ष 2019 में राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब उसे तीन पहिए की सरकार कहा गया था। आज नए गठबंधन बनने के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों के पास तीन-तीन पहिए हैं। फिर भी इस बात का अंदाज नहीं लग पा रहा है कि वे चलेंगे कैसे और जाएंगे किस तरफ, नए तालमेल में मत विभाजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जहां भी त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले होंगे, वहां स्थापित नेताओं को परेशानी तो होगी ही। बीते दिनों में राजनीति में वैमनस्य का जहर इतना अधिक घोल दिया गया है कि परदे के पीछे भी समझौता करना आसान नहीं है। अब आने वाले दिनों में चाहे जितनी सभाएं कर ली जाएं, चाहे जितना जहर एक-दूसरे के खिलाफ उगल लिया जाए, चुनावी परिणाम तो वही होंगे जो मतदाता को नेताओं की बगावत के समय समझ में आया था। पिछली सरकार से नई सरकार बेहतर काम कर रही है, यह समझा पाना और उस पर राय बनना फिलहाल मुश्किल है। इसके बीच इतना तय है कि अब चुनावी समर में संघर्ष मूल अस्तित्व बचाने से लेकर नए अस्तित्व को बचाए रखने के बीच होगा, जहां नेताओं की महत्वाकांक्षा और मतदाताओं की अपेक्षा फैसला सुनाएगी।

हिन्द स्वराज्य

हिन्दुस्तान की दशा-1 (भाग-2)

गतांक से आगे...

प्रश्न- इससे तो मालूम होता है कि आप पाखंडी बनने की तालीम देते हैं। धर्म के बारे में ऐसी बातें करके ठग लोग दुनिया को ठगते आये हैं और आज भी ठग रहे हैं।

उत्तर- आप धर्म पर गलत आरोप लगाते हैं। पाखंड तो सब धर्ममि है। जहाँ सूरज है वहाँ अंधेरा रहता ही है। परछाई हर एक चीज के साथ जुड़ी रहती है। धार्मिक ठगों को आप दुनियावी टगो से अच्छे पायेंगे। सभ्यता में जो पाखंड मैं आपको बता चुका हूँ, वैसा पाखंड धर्म में मैंने कभी नहीं देखा।

प्रश्न- यह कैसे कहा जा सकता है? धर्म के नाम पर हिन्दू-मुसलमान लड़े, धर्म के नाम पर ईसाइयों में बड़े-बड़े युद्ध हुए। धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाह लोग मारे गये, उन्हें जला दिया गया, उन पर बड़ी-बड़ी मुसीबत गुजारी गयीं। यह तो सभ्यता से बदतर ही माना जायेगा।

उत्तर-तो मैं कहूँगा कि यह सब सभ्यता के दुख से ज्यादा बरदाश्त हो सकने जैसा है। आपने जो कुछ कहा वह पाखंड है, ऐसा सब लोग समझते हैं। इसलिए पाखंड में फँसे हुए लोग मर गये कि सारा सवाल हल हो गया। जहाँ भोले लोग हैं वहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन उसका असर हमेशा के लिए बुरा नहीं रहता। सभ्यता की होली में जो लोग जल मरे हैं, उनकी तो कोई हद ही नहीं है। उसकी खूबी यह है कि लोग उसे अच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। फिर वे न तो रहते दीन के और न रहते दुनिया के। वे सच बात को बिलकुल भूल जाते हैं। सभ्यता चूहे की तरह फूँककर काटती है। उसका असर जब हम जानेंगे तब पुराने वहम के मुकाबले में हमें मीठे लगेंगे। मेरा कहना यह नहीं कि हमें उन वहमों को कायम रखना चाहिए। नहीं, उनके खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही; लेकिन वह लड़ाई धर्म को भूलकर नहीं लड़ी जायेगी, बल्कि सही तौर पर धर्म को समझकर और उसकी रक्षा करके लड़ी जायेगी।

प्रश्न- तब तो आप यह भी कहेंगे कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में शान्ति का जो सुख हमें दिया है वह बेकार है।

उत्तर- आप भले शान्ति देखते हों, पर मैं तो शान्ति का सुख नहीं देखता।

क्रमश: ...

इंडिया गठबंधन जनता पार्टी के परिणाम दोहराएगा ?

मणेन्द्र मिश्रा 'मशाल'

लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता के इंडिया महागठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक सम्पन्न हुई। ऐसे में यह सवाल उभरकर सामने आ रहा है कि क्या पचास साल पूर्व केंद्र की सत्ता के खिलाफ जनता पार्टी जैसी एकता इंडिया के रूप में दिखेगी? यह सवाल इसलिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि विपक्षी दलों ने अनेक असहमतियों के बाद भी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को धरातल पर ला दिया। पिछले दोनों आम चुनाव में एनडीए गठबंधन ने विपक्षी दलों के आधार वोट बैंक में सेंधमारी कर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस के सिकुड़ने और क्षेत्रीय दलों के व्यापक विस्तार न होने से पूरे देश में विपक्षी दलों को सत्ता में वापसी के लिए एकजुट होना पड़ा।

हिन्दी पट्टी में भाजपा की मजबूती का बड़ा कारण धार्मिक मुद्दों पर उसकी परंपरागत राजनीति है जिसकी पृष्ठभूमि में आरएसएस एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तर भारत में अस्मितावादी राजनीति कर रही अनेक पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले राजनैतिक दलों के साथ गठबंधन कर भाजपा सत्ता में बने रहने का रास्ता मजबूत करती रहती है। इससे विपक्षी दलों के विचार और अभियान आम जनता में प्रभावी तरीके से नहीं फैल पा रहे हैं। जातीय आधार को सहेजते हुए अपने समाज के नायकों का नाम जोड़कर अस्तित्व में आ रहे अनेक स्थानीय दल स्थापित दलों के आधार को प्रभावित कर रहे हैं। इस रणनीति की तोड़ के संदर्भ में इंडिया गठबंधन की संकल्पना को समझा जा सकता है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनेक घटनाओं से सामाजिक संतुलन बिगड़ता दिखा। कोविड की दूसरी लहर से मध्य वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग की समस्याओं ने विकराल रूप लिया जिसमें महंगाई और बेरोजगारी भी बड़े कारक रहे। नौकरियों में छटनीं, माइग्रेशन और कोविड के बाद उपजी बीमारियों के महंगे इलाज से भारत में एक ऐसा नया वर्ग उभरा है जो अचानक से गरीबी के दायरे में आ गया है। हालांकि इनके लिए केंद्र सरकार ने कई लाभकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें राहत देने का प्रयास किया, लेकिन वह सुविधा ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को ही चरितार्थ कर रही है। विपक्षी दल इन लक्षित समूहों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस आक्रोशित मतदाता समूह को

जहां विपक्षी दल अपने पाले में करने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं वहीं सत्ताधारी दल इन्हें लाभार्थी वर्ग के रूप में अपना बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की एकता में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मुद्दों पर एक आम राय की भी भूमिका है जिसमें नागरिकता संशोधन कानून एक प्रमुख बिन्दु है।एनआरसी/सीएए को लेकर हुए आंदोलन को कई प्रकार से विपक्षी दलों का समर्थन मिला। उस दौरान शाहीन बाग के आंदोलन की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक फैली। इसी प्रकार तीन कृषि कानून की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा किसान आंदोलन हुआ जिसका परिणाम किसान कानून स्थगन के रूप में आया। दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों में विशेषकर जाट समुदाय की एकजुटता ने केंद्र सरकार को दबाव में ला दिया। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के प्रति एक नकारात्मक माहौल बना, फिर भी विपक्षी दलों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया।

नागरिकता संशोधन विधेयक में बदलाव और किसान आंदोलन को जिस प्रकार सिविल सोसाइटी सहित अकादमिक जगत के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, समाजसेवियों एवं संस्कृतिकर्मियों का समर्थन मिला, वह 50 वर्ष पूर्व के छात्र आंदोलन की भांति ही है। 70 के दशक में गुजरात में मेस की बढ़ी हुई फीस को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन का फैलाव बिहार, यूपी सहित पूरे देश में हुआ। बिहार की राजधानी पटना के कदम कुआं के हास्पिटल में इलाज करा रहे लोकनायक जय प्रकाश नारायण द्वारा आन्दोलनरत छात्रों को मार्गदर्शन एवं संरक्षण देने से छात्रों का संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हो गया। इस कारण तत्कालीन इंदिरा सरकार के विरुद्ध एक व्यापक जनमत तैयार हुआ। शुरू में विभिन्न दलों की एकता जनता परिवार के रूप में संगठित हुई जो बाद में जनता पार्टी के रूप में आकार लेने लगी। 1974 में केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन 77 में जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में देखने को मिला था। उसी प्रकार की परिस्थितियाँ आज दिखती प्रतीत हो रहीं हैं जिसमें इंडिया गठबंधन केन्द्रीय भूमिका में हैं। दो महीने पूर्व बिहार के पटना में विपक्षी राजनैतिक दलों की बैठक हुई जिसमें कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में देश के अनेक राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा जिसमें केंद्र से भाजपा सरकार को हटाने के लिए पूरे देश में विपक्षी एकता पर आम सहमति बनी। इसका असर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के समर्थन से कांग्रेस की जीत के रूप में दिखा। हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र में राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से भी गठबंधन दलों में उत्साह बढ़ा। उनके सदन में भाषण से विपक्षी दल और इंडिया चर्चा के केंद्र में आ गए। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक कर्नाटक के बेंगलुरू में हुई जिसमें विपक्षी एकता के लिए इंडिया नाम प्रस्तावित हुआ।

इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिव इन्क्लूसिव अलायंस) है। वस्तुत: इंडिया के माध्यम से विपक्षी दलों ने बीजेपी के राष्ट्रवाद का विकल्प दिया है। जिसमें मूल रूप से समाज का उपेक्षित और कमजोर समाज है, जिसे संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ग को खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के सदस्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) से संबोधित कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद इसकी अगली बैठक मुंबई में हुई जिसमें 28 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में चौदह सदस्यीय समन्वय समिति बनी जिसमें जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया गठबंधन का नारा बना। साथ ही लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया गया। इसी प्रकार के एजेंडा और सहमति पत्र की घोषणा जनता पार्टी के समय हुई थी। इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक पहले घरेलू सिलेंडर के दामों में कमी के साथ संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का फैसला केंद्र सरकार पर चुनावी दबाव के रूप में भी देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है विपक्षी दल केंद्र सरकार के फैसलों को तानाशाही बताते हुए अघोषित आपातकाल लागू होने की बात कह रहे हैं जबकि भाजपा अपने सहयोगी दलों को जोड़े रखने में पूरी ऊर्जा लगा रही है। ऐसे में इंडिया और जनता पार्टी की परिस्थितियों के आधार पर चुनावी परिणाम में एकरूपता रहेगी या जनता पार्टी के विजय की तरह इंडिया उसे दोहराएगा।

एक देश-एक चुनाव: भाजपा ने बिछा दी बड़ी सियासी बिसात

आशीष तिवारी

एक देश एक चुनाव के लिए गठित की गई कमेटी से भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी सियासी बिसात बिछा दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की ओर से चले गए इस दांव को कोई भी राजनीतिक दल खुलकर खारिज नहीं कर सकता। क्योंकि अलग-अलग होने वाले चुनावों से जनता भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। सियासी गलियारों में तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चले गए इस दांव को बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक से मिले सियासी लाभ की तरह बताया जा रहा है। हालांकि अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू हो गई तो क्षेत्रीय दलों के लिए सियासी तौर पर बड़े संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर जनता की पल्स को समझते हुए बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। फिलहाल एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए बनाई गई कमेटी से देश की सियासत में उबाल आ गया है। सेंटर फॉर पॉलीटिकल स्ट्रेटजी एंड एलायंसेज के डायरेक्टर हरमीत सिंह कहते हैं कि एक देश एक चुनाव वह पब्लिक इंट्रेस्ट का मुद्दा है जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करता आया है। हरमीत सिंह कहते हैं कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि देश में अलग-अलग चुनाव नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि सियासी नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदे का मुद्दा माना जा सकता है। क्योंकि यह मुद्दा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहता है। वह कहते हैं कि उनकी ओर से लगातार ऐसे तमाम सियासी मुद्दों को लेकर सर्वे भी होते रहे हैं। 2014 और 2019 में किए गए ऐसे सर्वे में यह बात प्रमुखता से सामने आई थी कि हर साल होने वाले अलग-अलग चुनावों से बेहतर है कि एक बार ही चुनाव कराया जाए। इससे लोगों के समय की भी बचत होगी और सरकारी इंतजामों पर होने वाले खर्च मे भी भारी कटौती हो सकेगी। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक देवेश चतुर्वेदी कहते हैं कि वैसे तो यह फैसला सियासी तौर पर बड़ी चुनौतियां वाला है। क्योंकि इसके लिए क्षेत्रीय संगठन खुलकर समर्थन करने से कतरा सकते हैं। इसके पीछे वह तर्क देते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के मुद्दे पूरी तरह से अलग होते हैं। चूंकि क्षेत्रीय दल हमेशा स्थानीय मुद्दे और विधानसभा के लिहाज से चुनावी तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो मुद्दों की राजनीति में क्षेत्रीय दल खुद को इतना मजबूत नहीं पाएंगे। इसके अलावा देवेश चतुर्वेदी कहते हैं कि सदन में अगर इस पर प्रस्ताव को लाया जाता है तो यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा इसमें साथ देश के अलग-अलग राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ेगी। सियासी जानकारों का कहना है यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता आंख बंद करके समर्थन करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाना उनके लिए न सिर्फ बड़ा सियासी दांव है बल्कि आने वाले चुनाव में इसको गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण हरिओम तंवर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी साल में एक देश एक चुनाव की बात को उठाकर सियासत में फिलहाल बड़ी हलचल तो पैदा ही कर दी है। उनका मानना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुनावी मैदान में भी जनमत संग्रह करती है तो भी उसको जमकर समर्थन मिलना तय है। क्योंकि अलग-अलग एजेंसियों और सियासी दलों की और से उठाए जाने वाले इन मुद्दों पर जनता की राय तकरीबन एक सी ही सामने आई है। राजनीति के जानकारों का मानना यह भी है कि एक देश, एक चुनाव अगर देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में आमतौर पर मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं।

लवली के लिए बड़ी चुनौती, आप सहयोगी भी विरोधी भी

गुलशन राय खत्री

लंबी जद्दोजहद के बाद भले ही कांग्रेस आलाकमान ने अरविंदर सिंह लवली पर भरोसा जताते हुए दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप दी हो लेकिन लवली के लिए ये पद से अधिक कांटों का ताज है। उन्हें एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें उसे एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन आई एन डी आई ए के सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ रहते हुए भी उसी से अपना वोट बैंक वापस हासिल करना है। यही नहीं, उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ बिखर चुके संगठन को एकजुट करना होगा बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही पब्लिक का भी भरोसा जीतना होगा। ऐसे में आने वाले दिन लवली के लिए बड़ी चुनौती होंगे। पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी को लेकर जो रुख है, उसके विपरीत रुख दिल्ली में अपनाना आसान नहीं है। दरअसल, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी मोर्चे के रूप में जो गठबंधन बनाया गया है, उसमें आम आदमी भी शामिल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट बैंक छीना है और उसी के बलबूते वह लगातार तीन बार से सत्ता में है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार करें या फिर पार्टी नेतृत्व को देखते हुए उसके प्रति नरम रुख अपनाएं। अगर लवली, आम आदमी पार्टी पर आक्रामक हमले करते हैं तो जाहिर है कि इसका असर राष्ट्रीय् स्तर पर बन रहे विपक्षी मोर्चे पर पड़ेगा और ये भी संभावना है कि पार्टी आलाकमान ही लवली को एक सीमा के बाद आक्रमक रुख अपनाने से रोके। इसके विपरीत अगर लवली, आप के प्रति नरम रवैया अपनाते है तो वह सत्ता में आना तो दूर विपक्षी दर का रुतबा भी हासिल नहीं कर सकेंगे। वैसे भी अब लोकसभा चुनाव में एक वर्ष से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में लवली को एकसाथ कई चुनौतियों से जूझना होगा। 2013 में दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह गिरना शुरू हुआ, उसके बाद अब तक नहीं संभला। अब हालत ये हो गई है कि विधानसभा चुनाव जीतना तो दूर, अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में लवली की सबसे पहली चुनौती तो गुटों में बंट चुके अपने ही संगठन को एकजुट करने की है। खासकर उन नेताओं को एकसाथ लाने की जरुरत है, जो अब तक प्रदेश कार्यालय की ओर आने को ही तैयार नहीं थे। उन्हें न सिर्फ उन्हें सभी गुट के नेताओं को एकसाथ लेकर चलना और उनमें बैलेंस बनाना कम सरदर्द वाला नहीं होगा। लेकिन लवली के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हारून यूसुफ का कहना है कि चुनौती ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलना है या खिलाफ, बड़ी चुनौती संगठन को खड़ा करने की है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इसी तरह की चुनौती राजीव गांधी के वक्त भी आयी थी। उन्होंने वर्करों से कहा था कि अलायंस भले ही किसी से हो लेकिन अगर अलायंस का कोई दल गड़बड़ी कर रहा है तो उसे उठाया ही जाना चाहिए। अब भी वही स्थिति है। आप भले ही इंडिया अलायंस में हो लेकिन अगर वह कुछ गलती करती है तो हमारे मुंह पर किसी ने पट्टी थोड़ा ही बांधी है। वैसे भी पार्टी आलाकमान ने कभी भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से तो नहीं रोका। ऐसे में चुनौती आम आदमी पार्टी के अलायंस में होने की नहीं बल्कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की है। जिस दिन दिल्ली में पार्टी का संगठन खड़ा हो जाएगा, उसी दिन पार्टी का वोट बैंक भी लौट आएगा।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजनीतिक यात्रा

समीर चौगांवकर

राजस्थान में सरकार बनाने और मध्य प्रदेश में सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक यात्राओं के द्वारा जनसमर्थन हासिल करने की रणनीति बनाई है। राजस्थान में भाजपा 2 सितंबर से चार बड़े धार्मिक स्थानों से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, वहीं मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा विंध्य में चित्रकूट से शुरू करेगी। राजस्थान की यात्राओं में खास बात यह है कि राजस्थान में हुई पिछली 2 यात्राओं की कमान और चेहरा वसुंधरा राजे थी, लेकिन इस बार न ही वसुंधरा के हाथ में कमान है और न ही उनका चेहरा पार्टी ने आगे किया है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाया गया है। इसका संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनने पर भाजपा किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने का मन बना चुकी है।

उल्लेखनीय है कि 2002 में राजस्थान में वसुंधरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वसुंधरा राजे ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जिसका असर यह हुआ कि 2003 में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2008 में भाजपा को राजस्थान में नेताओं की आपसी खींचतान के कारण हार का सामना करना पड़ा। 2013 में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ फिर से वसुंधरा राजे ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस ने भी सत्ता में रहते हुए 2013 में मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान के नेतृत्व में यात्रा निकाली थी लेकिन जब दिसंबर-2013 में चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस बुरी तरह हारी थी।

राजस्थान में पहली यात्रा 2 सितंबर को पूर्वी राजस्थान रणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरु होगी जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्?डा हरी झंडी दिखाएंगे। 18 दिन और 1847 किलोमीटर चलने वाली यह यात्रा सवाई माधोपुर, जयपुर व भरतपुर क्षेत्र की कुल 47 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन पूर्वी राजस्थान में बेहद कमजोर रहा था।

धौलपुर जिले में बीजेपी ने सिर्फ एक सीट जीती थी लेकिन राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने के कारण बीजेपी ने उस विधायक को भी पार्टी से निकाल दिया था। दूसरी यात्रा 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) से गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। बेणेश्वर धाम दक्षिण राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह यात्रा 19 दिन में 2433 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इस यात्रा में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा (जैसलमेर) से शुरू होकर 18 दिन में 3574 किलोमीटर की यात्रा में जैसलमेर, जोधपुर, पोकरण, मेड़ता, डेगाना, शेरगढ़, बिलाड़ा, अजमेर, पुष्कर, नागौर सहित करीब 51 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। पश्चिमी राजस्थान में रामदेवरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। भाजपा यहां मेघवाल, जाट, कुमावत, माली जैसे बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। इस यात्रा को राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएगे। चौथी यात्रा गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) से शुरू होगी। 18 दिनों में 2128 किलोमीटर में 50 विधानसभा को कवर करने वाली इस यात्रा को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। इस यात्रा में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर व अलवर जिलों की विधानसभा सीटें आएंगी। लोकदेवता गोगाजी को उत्तरी राजस्थान में भगवान स्वरूप में पूजा जाता है।

राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी भाजपा पांच यात्राएं निकालेगी। 3 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश से निकलने वाली पांचों यात्राएं 10 हजार 543 किलोमीटर का सफर कर 210 विधानसभाओं को कवर करेगी। यात्राओं के इस सफर के दौरान मध्यप्रदेश में 211 बड़ी सभाएं, 678 छोटी सभाएं होगी। 998 स्थानों पर यात्राओं का स्वागत और नुक्कड़ सभाएं होगी। 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में यात्राओं का समापन होगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 सितंबर को चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर में पूजा करने के बाद भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरूआत करेंगे। यह यात्रा 12 जिलों के 48 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। यह यात्रा 19 दिन में 2343 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 5 सितबंर को महाकौशल के मंडला से शुरू होने वाली दूसरी यात्रा को भी अमित शाह रवाना करेंगे। यह यात्रा 18 दिन में 2303 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 10 जिलों की 45 विधानसभा सीटों से गुजरेगी।

तीसरी यात्रा 4 सितंबर को खंडवा से धूनीवाले बाबा का आशीर्वाद लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। यह यात्रा 21 दिन में 2,000 किलोमीटर के सफर में 10 जिलों के 42 विधानसभाओं से गुजरेगी। चौथी यात्रा को भी हरी झंडी नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 सितंबर को दिखाएंगे। 17 दिनों में 2,000 किलोमीटर तय करने वाली यह यात्रा 12 जिलो के 44 विधानसभाओं को कवर करेगी। पांचवी और अंतिम यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर कस्बे से 6 सितंबर को जेपी नड्डा शुरू करेंगे। 17 दिन में 1997 किलोमीटर का सफर करने वाली यह यात्रा 11 जिलो के 42 विधानसभाओं से गुजरेगी।

भाजपा की ये राजनीतिक यात्राएं कितनी फायदेमंद होती हैं यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे को अलग-थलग करके आगे बढ़ रही भाजपा कब तक वसुंधरा बिना प्रचार कर पाएगी, और जनता कितना रिस्पॉन्स देगी, यह यात्रा की सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज ने अपने मन को समझा लिया है कि चुनाव के बाद अगर सरकार आती है तो उन्हें किसी नए नेता के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है।

वायदे पूरा करने के स्रोत भी बताएं राजनीतिक दल

उमेश चतुर्वेदी

हाल में चुनाव सुधार की दिशा में जितने भी कदम उठे हैं, उनमें सबसे ज्यादा भूमिका या तो सर्वोच्च न्यायालय की रही है या फिर चुनाव आयोग की। तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने ही वाली है। इन चुनावों में वायदों की बाढ़ आना स्वाभाविक है। उसकी आहट दिखने भी लगी है। ऐसे में चुनाव आयोग के एक दिशा-निर्देश की याद आना स्वाभाविक है।

साल 2015 में चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनावी मैदान में उतरते वक्त मतदाताओं से वायदे करते राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि वे सत्ता में आने के बाद उन्हें किस स्रोत से पूरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग से यह उम्मीद रखी जा सकती है कि वह अपने उस दिशानिर्देश का पालन करवाने की शुरुआत करे।

भारत में चुनाव लोकप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत निर्वाचन आयोग कराता है। साल 1990 में जब टीएन शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए तो उन्होंने तब तक के उपलब्ध चुनाव कानूनों की बुनियाद पर ही चुनाव सुधार की दिशा में तब असंभव समझे जाने वाले कदम उठाए। इनके बाद पहली बार देश को अहसास हुआ कि चुनाव आयोग नामक कोई दमदार संस्था भी होती है, जो चाहे तो बंदूकों के दम पर बूथ लूटने वाले महाप्रतापी आपराधिक तत्वों पर लगाम लगा सकती है।

ऐसा नहीं कि चुनावों में धन और बाहुबल के प्रयोग, सत्ताधारी दल द्वारा प्रशासनिक मशीनरी के उपयोग को लेकर सवाल नहीं उठते थे। और शायद इसलिए भारतीय चुनावी परिदृश्य में शेषन के उभार के पहले भी चुनाव सुधार के लिए न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी जैसी उच्च समितियां गठित हुईं। इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें भी दीं, मगर बात आगे नहीं बढ़ी।

शेषन के बाद अगर चुनाव सुधार में प्रभावी पहल दिखती भी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बड़ी भूमिका है। उसने इस दिशा में सबसे अहम फैसला साल 2002 में दिया, जिसके तहत चुनावों के उम्मीदवारों के लिए आपराधिक मामलों, देनदारी, कर्ज, संपत्ति आदि की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया।

इसी कड़ी में सर्वोच्च अदालत का सबसे अहम फैसला 13 फरवरी, 2020 को आया, जिसमें उसने संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों के पूरे आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया, और दिशा-निर्देश जारी किया। सभी उम्मीदवारों और उनके परिवार की आर्थिक हैसियत को लेकर हलफनामा देना भी अनिवार्य कर दिया गया।

बहरहाल 2020 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उम्मीदवारों के चयन का आधार उसकी योग्यता और उपलब्धियां होनी चाहिए, जीतने की संभावना नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलों के लिए अब भी सबसे पहली योग्यता उम्मीदवार के जीतने की संभावना ही ज्यादा होती है। वैसे कहा जा सकता है

कि इस फैसले के आलोक में चुनाव आयोग ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं जारी कर पाया है, जिससे राजनीतिक दल उम्मीदवारों की योग्यता और उपलब्धियों पर जोर दे सकें। आयोग ऐसी व्यवस्था भी नहीं बना सका है, जिससे उम्मीदवार के येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की संभावना को महत्वहीन किया जा सके।

इसके बावजूद कह सकते हैं कि देश में जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं, वे चुनाव आयोग को अब तक प्राप्त कानूनी और संवैधानिक ताकतों के दायरे में ही हुए हैं। बेशक सर्वोच्च अदालत ने इसमें वक्त-वक्त पर हस्तक्षेपकारी भूमिका जरूर निभाई है। इन्हीं संदर्भों में चुनाव आयोग पर ही एक बार प्रबुद्ध लोगों की निगाह है। जिस तरह वक्त और हैसियत से आगे निकलकर राजनीतिक दल जनता को सुविधाएं देने के लिए वायदों का पिटारा खोल रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं।

मुफ्त देने के वायदे के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तो आ गई, लेकिन अब उसके बोर्डों और निगमों को पैसे की कमी से जूझना पड़ रहा है। पंजाब राज्य परिवहन निगम का घाटा बढ़ता जा रहा है। राज्य बिजली बोर्ड को लेकर राज्य सरकार के दावे और हकीकत में अंतर है। पंजाब में हर महिला को हजार रुपये देने का वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया।

यही हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली परिवहन निगम में सालों से नयी बसें नहीं आयीं और निगम करीब 45 हजार करोड़ के घाटे में है। यही स्थित दिल्ली जल बोर्ड की है, जो 70 हजार करोड़ के घाटे में है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना लागू करना भी कठिन हो गया है। हिमाचल में भी पुरानी पेंशन और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई।

लेकिन बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते उसे भी इन वायदों को लागू करना मुश्किल पड़ता जा रहा है। मई में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पांच गारंटियों का वादा करके जीत गई। लेकिन अब गारंटी पूरा करना उसके लिए कठिन होता जा रहा है। सामान्य विकास के लिए भी धन की कमी पड़ती जा रही है।

इस बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वायदों की झड़ी लग रही है। राजस्थान में भविष्य में कांग्रेस की ओर से युवाओं को लैपटॉप मिलना है तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को हजार रुपये महीना मिलने लगा है। लेकिन यह भी सच है कि इसका दबाव दोनों ही राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना का कांग्रेस ने वादा किया, लेकिन उसे लागू करना उसके लिए भी चुनौती बना हुआ है।

हम जिस दौर में रह रहे हैं, उसमें सत्ता और पद ही व्यक्ति और राजनीतिक दलों के रसूख का पैमाना बन गया है। इसलिए हर दल को अगर वायदों का पिटारा खोलना पड़ता है तो वे खोलते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अंततः घाटा जनता को ही होता है। या तो उसके साथ किए वायदे पूरा नहीं हो पाते या कुछ वर्गों के वायदे पूरे भी हो जाते हैं, तो बाकी वर्ग को उसका भार झेलना होता है। अनाप-शनाप वायदों को कई बार जन-दबाव में पूरा भी किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट समूचे राज्य के आर्थिक तंत्र पर पड़ता है, और प्रकारांतर से आम लोगों को ही झेलना पड़ता है। चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ते रहे चुनाव आयोग को साल 2015 के अपने दिशा-निर्देश को कड़ाई से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वह राजनीतिक दलों से यह जानने की कोशिश करे कि जो वायदे वे कर रहे हैं, आखिरकार वे किस स्रोत से पूरा करेंगे। राजनीतिक दलों पर ऐसा करने का दबाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर मतदाता भी इसके फायदे और नुकसान को समझ पाएंगे।

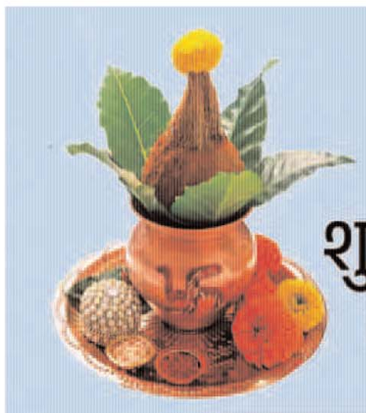

खरीदारी और नई शुरुआत के शुभ मुहूर्त

सर्वार्थसिद्धि योग....

3 सितंबर	सुबह 10:38 से अगले दिन सुबह 6.24 तक
5 सितंबर	सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह 6.24 तक
6 सितंबर	सुबह 6:24 से अगले दिन सुबह 6.24 तक
11 सितंबर	सुबह 6:24 से रात 8 बजे तक
12 सितंबर	सुबह 6:24 से रात 11 बजे तक
20 सितंबर	दोपहर 3 बजे से अगले दिन सुबह 6.27 तक
23 सितंबर	सुबह 6.27 से दोपहर 3.35 तक
24 सितंबर	दोपहर 1.42 से अगले दिन सुबह 6.27 तक
25 सितंबर	दोपहर 12 से अगले दिन सुबह 6.28 तक

ये योग भी खास

अमृत सिद्ध योग	20 सितंबर	दोपहर 3 बजे से अगले दिन सुबह 6.27 तक
द्विपुष्कर योग	26 सितंबर	सुबह 9:42 से रात 1:45 तक
त्रिपुष्कर योग	5 सितंबर	दोपहर 3.46 बजे से अगले दिन सुबह 6.24 तक
पुष्य नक्षत्र	10 सितंबर	शाम 5 से 11 सितंबर की रात 8 बजे तक

सितंबर 2023
इस महीने व्रत-पर्व के 18 दिन

सितंबर में व्रत-त्योहारों का विशेष योग बन रहा है। इस महीने का पहला हफ्ता श्रीकृष्ण जन्मोत्सव वाला रहेगा। वहीं, दूसरे सप्ताह में एकादशी और अमावस्या बड़े व्रत रहेंगे। तीसरे हफ्ते में गणेशोत्सव शुरू होगा। जो कि महीने के आखिरी तक रहेगा। सितंबर के आखिरी दिनों में ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। इस महीने सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और द्विपुष्कर जैसे बड़े शुभ योग भी रहेंगे।

पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र और काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी के मुताबिक 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन गणेश विसर्जन होगा। इसके अगले दिन यानी 29 सितंबर को स्नान दान पूर्णिमा है। इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की भी शुरुआत हो जाएगी।

कुल मिलाकर ये पूरा महीना खरीदारी और मांगलिक कामों के लिए खास रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इस महीने 5 शुक्रवार और इतने ही शनिवार रहेंगे। साथ ही महीने का पहला दिन शुक्रवार और आखिरी दिन शनिवार होगा। शुक्र और शनि के इस विशेष संयोग के चलते ये महीना समृद्धि दायक माना जा रहा है।

इस संयोग से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकारें बड़े फैसले लेंगी। बड़ी योजनएं बनेंगी और पुरानी योजनाओं पर काम भी शुरू होगा। सिंतबर में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। इसमें सूर्य अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र कर्क राशि में और बुध सिंह राशि में मार्गी होंगे। मंगल कन्या राशि में अस्त होंगे।

सितंबर के खास तीज-त्योहार

6 सितंबर
जन्माष्टमी स्मार्त

10 सितंबर
अजा एकादशी

14 सितंबर
भाद्रपद अमावस्या

17 सितंबर
कन्या संक्रांति

18 सितंबर
हरतालिका तीज

19-28 सितंबर
गणेशोत्सव

26 सितंबर
एकादशी

27 सितंबर
अनंत चतुर्दशी

29 सितंबर
प्रोष्ठपदी श्राद्ध

इन लोगों को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए तुलसी की माला

सनातन धर्म में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है। सभी लोग इसकी नियमानुसार पूजा-अर्चना भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि, तुलसी के पौधे के बराबर ही तुलसी की माला धारण का भी महत्व होता है। तुलसी की माला पहनने से इंसान को अनेक तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुलसी के माला के जुड़े नियमों को सही से फॉलो करें।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप विशेष फलदाई माना गया है। ऐसे में यदि आप तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तो मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसके अलावा मन में सकारात्मक विचारों का संचार बढ़ जाता है। आइए उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्र से जानते हैं तुलसी की माला से जुड़े नियम और किन लोगों को माला नहीं पहनना चाहिए।

इन लोगों को नहीं पहनना चाहिए तुलसी की माला

मांस-मंदिरा खाने वाले न पहनें मालाः यदि आप तुलसी का माला धारण करने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़े नियम भी जान लेना चाहिए। बता दें कि, यदि आप इस माला को धारण कर रहे हैं तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। ऐसे में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए।

रुद्राक्ष धारण करने वाले तुलसी न पहनेंः जिस व्यक्ति ने तुलसी की माला धारण की है, उसे भूल कर भी रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव उस व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं।

तुलसी की माला धारण करने के नियम

माला को बार-बार ना उतारें: ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के जुड़े कई नियम बताए गए हैं। यदि आपने एक बार तुलसी की माला धारण कर ली है। उसे बार-बार भूलकर भी नहीं उतारना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो पाना मुश्किल है।

माला का शुद्धीकरण जरूरी: तुलसी की माला धारण करने के पहले उसका शुद्धीकरण करना बेहद आवश्यक है। माला धारण करने से पहले उसे अच्छी तरह गंगाजल से धो लें। जब माला सूख जाए उसके बाद ही धारण करना चाहिए।

माला पहनकर शौचालय ना जाएं: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि आप गले में तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते, तो इसे दाएं हाथ में भी धारण किया जा सकता है। परंतु नित्य क्रिया के समय इस माला को उतार कर रख दें। स्नान करने के बाद इसे दोबारा गंगाजल से धोकर ही पहने।

क्या बाथरूम में लाल बाल्टी रखना अशुभ? वास्तु के अनुसार यह रंग सबसे ज्यादा शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार लोगों के घर में रखी चीजें उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। घर में वस्तुओं की दिशा, उन्हें रखने का तरीका और कलर व्यक्ति के जीवन पर काफी असर डालता है। चीजों का रंग लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर डालता है। घर को तरोताजा रखने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए वास्तु के रंगों का उचित संतुलन होना जरूरी है। बेडरूम, किचन और बालकनी समेत बाथरूम में भी वास्तु के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। बाथरूम में सही रंग की चीजें न रखने से घर में नेगेटिविटी फैल सकती है और लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार बाथरूम में किस रंग की बाल्टी रखना शुभ होता है और कौन सा रंग अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम की दिशा, उसकी दीवारों का रंग और उसमें रखी बाल्टी का रंग भी लोगों की जिंदगी पर काफी असर डाल सकता है। बाथरूम के लिए उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उसके बगल में नहीं होना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और सुख-शांति भंग हो सकती है। बाथरूम की दीवारों पर हमेशा हल्के रंग का पेंट करना चाहिए। अत्यधिक गहरे रंग का इस्तेमाल वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है। बाथरूम में रखने वाली बाल्टी का कलर भी वास्तु में काफी मायने रखता है और अत्यधिक गहरे कलर की बाल्टी व मग बाथरूम में नहीं रखना चाहिए।

बाथरूम में लाल रंग की बाल्टी रखना अशुभ?

बाथरूम में अत्यधिक गहरे रंग की बाल्टी और मग रखना अच्छा नहीं माना जाता है। लाल और काले रंग की बाल्टी बाथरूम में रखने से वास्तु दोष पैदा हो सकता है। ऐसा करने से धन हानि हो सकती है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लाल रंग को अग्नि का प्रतीक माना गया है, जिसकी वजह से इसे बाथरूम में रखने से बचना चाहिए। अगर आप बाथरूम में लाल रंग की बाल्टी और मग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द हल्के रंग की बाल्टी रखनी चाहिए और लाल रंग की बाल्टी बाहर निकाल देनी चाहिए। ऐसा करने से आप सुखी रहेंगे।

यहां लाल नहीं सांवले रंग में होती है हनुमान जी की पूजा

आप लोगों ने प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के बारे में कई कथाएं सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूरी रंग बहुत प्रिय है, इसी वजह से उनकी प्रतिमा भी सिंदूरी रंग में ही देखने को मिलती है। लेकिन आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकर आप बेहद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रतिमा सिंदूरी नहीं बल्कि श्याम रंग में है। जिसे देखकर आप एक पल के लिए आश्चर्य में डूब जाएंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला है या फिर शनिदेव महाराज की प्रतिमा सावले रंग में देखने को मिलती है। जानकार बताते हैं कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। अन्यथा हर जगह पर हनुमान जी की प्रतिमा सिंदूरी रंग में देखने को मिलती है। बता दें

यूपी के रायबरेली जनपद में शहर के इंडस्ट्रियल एरिया इलाके के भवानी पेपर मिल के पास बने अभय दाता मंदिर में हनुमान जी की सांवले रंग की प्रतिमा के आपको दर्शन करने को मिलेंगे, उन्होंने बताया कि इसका अपना एक अलग इतिहास है, वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्र बताते हैं, कि आपको इस तरह के हनुमान जी के दर्शन यूपी ही नहीं पूरे भारत ने शायद ही कहीं मिलें।

दूर-दूर से आते हैं श्रृद्धालु

इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, इस दौरान अभय दाता मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश मिश्र ने बताया कि मंगलवार और शनिवार को प्रदेश के कोने कोने से हनुमान जी के भक्त आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अभय दाता मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु गौरव वर्मा ने बताया कि अभय दाता मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां पर सच्चे मन से मानी गई हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।

घर में इस पौधे का उगना देता है पितृ दोष का संकेत

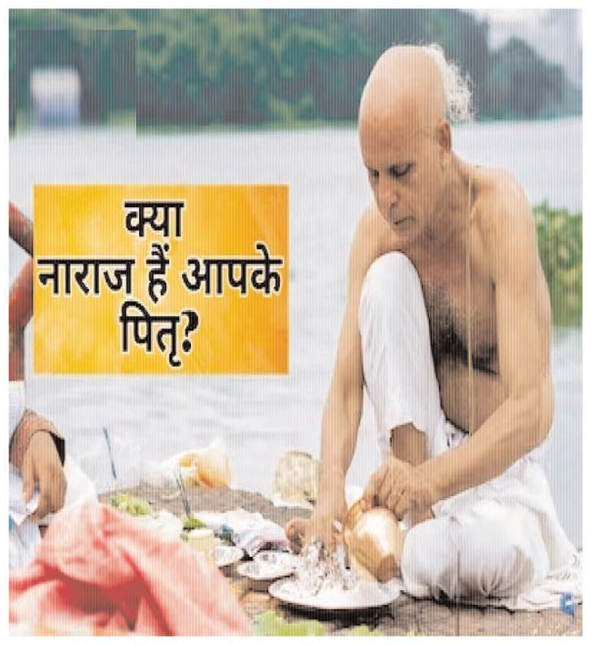

अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बिना किसी कारण अनेक समस्याएं आने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके पीछे पितृ दोष भी हो सकता है। कई घटनाएं ऐसे संकेत देती हैं जिससे सिद्ध होता है कि आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। इन घटनाओं का हमारे जीवन पर बेहद नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, घर के सभी सदस्यों की तरक्की में बधाएं उत्पन्न होने लगती हैं इसके अलावा मनुष्य के मान सम्मान में भी कमी आने लगती है। इन्हीं घटनाओं में से एक ऐसा पौधा है जिसका घर में उगना पितृ दोष का संकेत देता है।

इस पेड़ का उगना पितृ दोष के संकेत

पेड़ पौधे घर में लगाना शुभ होता है, परंतु बिना लगाएं पीपल का पेड़ घर में उग जाए तो पितृ दोष का संकेत माना जाता है। कहा जाता है जब आपके पितृ आपसे बेहद नाराज होते हैं तो आपके घर में पीपल का पेड़ उग जाता है।

पीपल के पेड़ से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, हिंदू धर्म में यह पौधा बेहद पूजनीय और शुभ माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करता है और दीप प्रज्वलित करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बन रहती है। यदि किसी व्यक्ति पर शनि देव की कुदृष्टि है तो उसे शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि आपके घर में किसी भी जगह पीपल का पौधा उग जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ आपसे बेहद नाराज है। जितनी जल्दी हो इसका निवारण करवाना चाहिए। जितनी जल्दी हो पितरों के तर्पण की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में पीपल का पेड़ उगना आने वाले भविष्य में परेशानियों का संकेत माना जाता है।

क्या करें पीपल के पेड़ का

पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार घर में पीपल का पौधा उग जाए तो उसे वहां से हटा देना उचित है। ज्योतिष के नियम के अनुसार पीपल के पौधे को हटाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले 45 दिनों तक पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और उसकी पूजा करें। 45 दिन के बाद उसे निकालकर किसी साफ और पवित्र स्थान पर लगा दें ऐसा करने से पीपल के वृक्ष का अपमान भी नहीं होगा और आपके ऊपर कृपा भी बनी रहेगी।

इस दिशा में पूजा करने से होती है धन प्राप्ति

पूर्व दिशा- पूर्व दिशा की तरफ मुख करके धार्मिक कार्य करना हमेशा लाभदायक होता है। यहां सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव अधिक होता है। इस दिशा से मान-सम्मान यश और ज्ञान मिलता है। जहां तक हो सके, पूजा-पाठ, ध्यान और पढ़ाई पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें।

पश्चिम दिशा- पश्चिम शनि की दिशा होती है। इस दिशा से रिश्ते, परिवार और खुशहाली प्रभावित होती है। इस दिशा की ओर भोजन करने से संघर्ष बढ़ता है। इस दिशा की ओर सिर करके सोने से स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक हानि भी होती है। इस दिशा में ध्यान और प्रार्थना करने से लाभ होता है।

उत्तर दिशा- धनधान्य के लिहाज से इस दिशा को खास माना जाता है। वास्तु के अनुसार, इस दिशा की ओर मुख करके किसी कार्य की शुरुआत और व्यवसाय करना सर्वोत्तम होता है। इस दिशा में देवी लक्ष्मी की उपासना करने से धन की प्राप्ति होती है।

दक्षिण दिशा- दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल और यम होते हैं। इस दिशा में दोष होने पर घर के सदस्यों में हमेशा अनबन रहती है। संपत्ति को लेकर भाई-बंधुओं में विवाद चलता रहता है। इस दिशा में हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलते हैं। यदि घर की इस दिशा में मंगल यंत्र स्थापित कर लिया जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगायी मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया । वन आवास एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज रात अपने निवास पर मीडिया प्रतिनिधियो को राज्य मंत्रिमंडल (केबिनेट)की बैठक में लिए गए फैसले के सम्बंध में जानकारी दी।

आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन है उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 एवं 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने की बड़ी घोषणा की गई । जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया।

डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 एवं 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुपालन में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसके तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।जिसमें आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चायत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउन्ट उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उपवर्गवार कट-ऑफ अंक जारी किए जाएंगे। साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा।

गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। स्व सहायता समूहों को 8 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2023 तक प्रति किलोग्राम कम्पोस्ट विक्रय पर एक रूपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि के मान से कुल 12.32 करोड़ रूपए तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे की दर से कुल 13.55 लाख रूपए प्रोत्साहन (बोनस) राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियन्ता के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

भारत स्काउट गाईड जिला संघ रायपुर को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम माठ, जिला रायपुर में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि या भू-भाटक को माफ कर निःशुल्क में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

* छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को शैक्षणिक (छात्रावास) तथा सामाजिक भवन के लिए ग्राम फुण्डहर, जिला रायपुर में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति जिला राजनांदगांव के स्वामित्व की भूमि को सशर्त आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

संस्था प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन पर आवंटित नजूल भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के द्वितीय अनुसूची के भाग- एक के स्पष्टीकरण में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत ग्रेड पे 8700 का वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल 15 में कोष्टिकाएं निर्धारण हेतु गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया।

सेरीखेड़ी में मंत्रालयीन सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी रायपुर में विकसित भूखण्डों के पात्रता में संशोधन का निर्णय लिया गया। योजना के लाभ की पात्रता सूची में न्यायिक सेवा श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों सहित अन्य को शामिल किया गया है।

वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये सीलबंद बोतलों में देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहागांव के गठन तथा नगर पंचायत माना-कैम्प को नगर पालिका में उन्नयन हेतु की गई घोषणा के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने करने का निर्णय लिया गया।

रंग हबीब का दो दिवसीय आयोजन राजधानी में शुरु

रायपुर। कला अकादमी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद रायपुर द्वारा रजा फाउंडेशन के सहयोग से विख्यात नाटककार और रंग निर्देशक हबीब तनवीर की जन्मशती पर दो दिवसीय शताब्दी समारोह ''रंग हबीब'' की शुरुआत शुक्रवार को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में हुई। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच रंगमंच के पुरोधा हबीब तनवीर के अवदान पर देश भर से पहुंचे प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जिसमें मुख्य रूप से वक्ताओं ने रंगमंच की शीर्षस्थ हस्ती हबीब तनवीर के जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत सरकार की ओर से किसी तरह की सांस्कृतिक पहल न किए जाने को दुखद बताया।

शुरूआत में स्वागत उद्बोधन देते हुए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन कला अकादमी के अध्यक्ष योगेंद्र त्रिपाठी ने आयोजन के उद्देश्य पर रोशनी डाली। सुबह पहला सत्र हबीब तनवीर के गीतों और रंग संगीत की प्रस्तुति से शुरू हुआ। जिसे नया थियेटर में सक्रिय रहीं वरिष्ठ रंगकर्मी व गायिका पूनम तिवारी ने अपनी बेटी के साथ कई हबीब तनवीर के रंगमंच से जुड़ी लोक रचनाएं प्रस्तुत की। खास तौर पर ''चोला माटी के राम'' की प्रस्तुति पर सभागार में उपस्थित लोगों ने खड़े हो कर अपना सम्मान व्यक्त किया। इस सत्र में प्रस्तावना वक्तव्य रखते हुए प्रख्यात संस्कृति कर्मी अशोक बाजपेयी ने कहा कि 20 वीं शताब्दी की कल्पना बिना हबीब तनवीर के अवदान को याद किए आप नहीं कर सकते। हबीब तनवीर एक ऐसे नायक निर्देशक थे, जिन्होंने अपने लोगों के साथ-साथ दूसरों के लिए भी रास्ते खोले। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदी अंचल में उनसे बड़ा रंग निर्देशक दूसरा कोई नहीं हुआ।

इसके बावजूद जन्मशताब्दी जैसे अवसर पर संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे केंद्रीय संस्थानों ने उन्हें भुला दिया।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने आदित्य एल-1 के लांच पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई

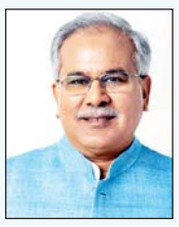

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसरो के प्रथम सूर्य मिशन आदित्य एल-1 के सफलतापूर्वक लांच पर इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान मिशन की सफलता के 10 दिन के अंदर ही इसरो की इस दूसरी बड़ी सफलता ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है।

इंदिरा बैंक खातेदारों की डूबी रकम वापसी के आसार, कन्हैया ने लिखा सीएम को पत्र

रायपुर। इंदिरा बैंक घोटाले की जांच में लगातार आई तेजी और घोटालेबाजों से मात्र एक महीने में ढाई करोड रुपए की वसूली किए जाने का स्वागत करते हुए इंदिरा बैंक संघर्ष समिति के अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ,शैलेश श्रीवास्तव ,शंकर सोनकर, श्रीमती नूरजहां और सुरेश बाफना ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए पत्र लिखकर इंदिरा बैंक के खातेदारों को उनकी डूबी हुई जमा राशि वापस कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमाकर्ताओं को राशि वापस दिलाई है इस तरह इंदिरा बैंक के खातेदारों को भी उनकी जमा राशि वापस दिलाने के लिए आदेश जारी करने की कृपा करेंगे। अग्रवाल ने कहा कि 2006 में घोटाले का शिकार हुई इंदिरा बैंक को डूबाने वालों से राशि वसूली की प्रक्रिया 12 वर्षों तक भाजपा की सरकार ने नहीं की थी, सरकार में बैठे लोग घोटालेबाजों को बचाने में लगे रहे इसलिए 12 वर्षों में एक रुपए भी राशि वसूल नहीं की जा सकी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी वसूली की कार्रवाई के बाद खातेदारों में रकम वापसी की उम्मीद बढ़ी है ,हम सभी निवेदन करते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व खातेदारों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश जारी होंगे।चुनाव पूर्व खातेदारों को रकम वापसी उनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा।

कृषि विवि में 4 को तिलहनी फसलों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद एवं इंडियन सोसायटी ऑफ आइलसीड रिसर्च, हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में 4 सितम्बर, 2023 को तिलहनी फसलों हेतु जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी एवं मूल्य संवर्धन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 5 एवं 6 सितम्बर को अलसी तथा कुसुम फसलों पर दो दिवसीय वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह करेंगे तथा अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि एवं पशु चिकित्सा, श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन) डॉ. संजीव गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर में तिलहनी फसलों पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों जैसे अलसी, सोयोबीन, कुसुम, राम तिल, तिल सरसों, मूंगफली, अरंडी आदि पर विशेषज्ञों द्वारा शोध पत्र भी प्रस्तुत किये जाएंगे। तिलहन फसलों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ ही 5 एवं 6 सितम्बर को अलसी तथा कुसुम फसलों पर दो दिवसीय वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

हाथकरघा उत्पादों में आधुनिक डिजाईन और नवीन रंग संयोजन को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ की वार्षिक आमसभा का आज राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुआ। इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ के विभिन्न जिले राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, रायगढ़, धमतरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर सहित महासमुन्द के लगभग 104 बुनकर सहकारी समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस अवसर पर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ श्री चन्द्रकांत वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निर्देशन में हाथकरघा संघ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने हाथकरघा उत्पादों को बाजार के अनुरूप बनाने के लिए आधुनिक डिजाईन एवं नवीन रंग संयोजन के प्रयोग को बढ़ावा देने जोर दिया और बुनकर समितियों को प्रोत्साहित भी किया। प्रबंध संचालक श्री वर्मा ने संघ के उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता के साथ लक्ष्य को समय-सीमा में पूर्ण करने की बात कही।

बैठक में सदस्यों द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक का अवलोकन कर वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट का भी अनुमोदन किया। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ के अंतर्गत उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में बुनकर सहकारी समितियों ने विस्तार से चर्चा की। संघ के सदस्य समितियों द्वारा बुनकरों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्ययोजना बनाने के सुझाव दिये। इसके साथ-साथ हाथकरघा संघ के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की। वार्षिक आमसभा की बैठक में पंजीयक सहकारी संस्था के श्री हितेश दोषी, ग्रामोद्योग की श्रीमती नूतन अजगर, उप संचालक श्री आई.आर.सिंह सहित हाथकरघा संघ के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री ए. अयाज महाप्रबंधक और श्री समीर मिश्रा ने आभार प्रदर्शन किया।

2 दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने ली बैठक, कई विषयों पर हुई चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा वर्ष 2023 की प्रादेशिक सम्मेलन के लिए होटल महिंद्रा में बैठक आयोजित किया गया. इस बैठक में आयोजन की तिथि, जगह के साथ, सत्र का विषय, साहित्यकार के आलावा शब्दकोश निर्माण की गतिविधि के ऊपर चर्चा की गई. बैठक आयोग के सचिव डॉ. अनिल भतपहरी के संयोजन मे आयोजित की गई। बैठक में आयोग द्वारा प्रादेशिक सम्मेलन के लिए 23 और 24 सितम्बर तय किया गया. ये दो दिन का आयोजन होटल बेबीलोंन इंटरनेशनल वीआईपी रोड रायपुर में किया जाएगा. इस सम्मलेन में छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, साहित्य की परिचर्चा की जाएगी. बैठक में प्रमुख रूप से भाषाविद और कुलपति डॉ. केसरी लाल वर्मा, साहित्यकार डॉ. पी सी लाल यादव, सरला शर्मा, डॉ दादू लाल जोशी, डॉ जे आर सोनी, मंगत रविन्द्र, कवि मीर अली मीर, काशीपुरी कुंदन, डॉ. सुधीर शर्मा मौजूद रहे।

ओलंपियाड प्रशिक्षण जनजाति विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए बनाएगा सक्षमः श्रीमती आबिदी

रायपुर। आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा है कि ओलंपियाड प्रशिक्षण जनजाति विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु सक्षम बनाएगा। श्रीमती आबिदी ओलंपियाड परीक्षा की तकनीक, पैटर्न और अध्यापन के तरीके लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विज्ञान और गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रही थी। प्रशिक्षण का आयोजन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा 1 और 2 सितंबर को नवा रायपुर के आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर में किया गया। प्रशिक्षण में 205 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए।

प्रशिक्षण का शुभारंभ आदिम जाति, अनुसूचित जाति विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने किया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को अपने विद्यालय के स्टूडेंट्स को ओलंपियाड परीक्षा की तकनीक, पैटर्न और अध्यापन के तरीके बताए गए। यह प्रशिक्षण दिल्ली से साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षित शिक्षक अपने जिले में जाकर अन्य सभी शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे और शिक्षकों द्वारा स्कूल के बच्चों को ओलंपियाड परीक्षा की भी तैयारी कराएंगे।

ज्ञातव्य है कि ओलंपियाड परीक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिससे स्टूडेंट्स की प्रतिभा विकास को बल मिलता है और पहचान मिलती है। इस परीक्षा के माध्यम से एकलव्य स्कूल के जनजातीय बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने और उन्हें उपलब्धि हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा।

अगस्त-सितम्बर में बिजली की खपत बढ़ा 1000 प्रतिशत, उद्योगों में जरुरत होने पर की जाएगी बिजली कटौती : अंकित आनंद

- **उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व उद्योग चेम्बर का प्रतिनिधिमंडल मिला सी.एस.पी.डी.सी.एल चेयरमेन से**

रायपुर। उरला-सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में अघौषित विद्युत कटौती के संबंध में शनिवार की दोपहर 3 बजे सी.एस.पी.डी.सी.एल. के चेयरमेन अंकित आनंद के साथ उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं उद्योग चेम्बर का प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। चेयरमेन आनंद ने इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि अगस्त-सितम्बर में बिजली की खपत बढ़ा 1000 प्रतिशत है इस कारण बिजली की कटौती की जा रही है, आगामी दिनों उद्योगों में जरुरत होने पर ही बिजली कटौती की जाएगी।

अगस्त-सितम्बर में बिजली की खपत बढ़ा 1000 प्रतिशत, उद्योगों में जरुरत होने पर की जाएगी बिजली कटौती - अंकित आनंद

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं उद्योग चेम्बर के अध्यक्ष श्री अश्विन गर्ग ने चेयरमेन को बताया कि पिछले कई दिनों से उरला-सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रों में बिना पूर्व सूचना अनियमित विद्युत कटौती सी.एस.पी.डी.सी.एल. के द्वारा की जा रही है। इसकी वजह से प्रदेश के सबसे पूराने एवं बड़े औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादन पूरी तरह ठप्प हो गया है। इससे उद्योगो को भारी नुकसान हो रहा है। बिजली विभाग के राजस्व का सबसें बड़ा स्त्रोत उद्योग ही है फिर भी बिजली संकट के समय सबसे पहले बिजली कटौती उरला-सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रों मे ही की जाती है। जब भी बिजली संकट आया है उद्योगपतियों ने हमेशा विभाग का साथ दिया है। हमारा आपसे यह आग्रह है कि बिजली संकट की स्थिति का सामना करने हेतु एक अपातकालीन योजना बनायी जानी चाहिए एवं प्रदेश में समान रुप से विद्युत कटौती की जानी चाहिए न की पूरे प्रदेश का भार हमारे औद्योगिक क्षेत्र में डाल दिया जायें।

चेयरमेन अंकित आनंद जी ने बताया कि बारिश कम होने की वजह से पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में बिजली की खपत लगभग 1000 प्रतिशत बढ गयी है, हमारा उत्पादन लगभग 350 प्रतिशत बढा है। इस वजह से बिजली कटौती करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा बिजली कटौती न्युनतम करने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है एवं उद्योगों में सायं 5 बजे से रात 11 बजे तक ही जरुरत होने पर बिजली कटौती की जायेगी।

बैठक में सी.एस.पी.डी.सी.एल. के प्रबंध संचालक मनोज खरे, संचालक श्रीमति उज्जवला बघेल, उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं छ.ग. उद्योग चेम्बर से अश्विन गर्ग, नीरज अग्रवाल, स्पंज आयरन एसोसिएशन से अनिल नचरानी, मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन से विकास अग्रवाल, विष्णु जिंदल, छ.ग. रोलिंग मिल एसोसिएशन से संजय त्रिपाठी व बांके बिहारी अग्रवाल उपस्थित थे।

क्यों खैरागढ़ में भाजपा ने विक्रांत सिंह पर किया भरोसा?

खैरागढ़ छुईखदान गंडई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें है। इसमें से एक नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई भी है। इसमें खैरागढ़ विधानसभा सीट बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने इस बार युवा कार्यकर्ता को इस सीट पर मौका दिया है। विक्रांत सिंह को इस बार टिकट दिया गया है। विक्रांत सिंह रमन सिंह के भतीजे हैं। पिछले तीन बार से विक्रांत टिकट की आस में थे। इस बार बीजेपी ने उनपर खैरागढ़ सीट के लिए भरोसा जताया है।

जातिगत समीकरण- काफी समय से खैरागढ़ वासी इसे जिला बनाने की मांग कर रहे थे। ये पहले राजनांदगांव के अंतर्गत पड़ता था। हालांकि साल 2022 में हुए उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने जीत प्रमाण पत्र मिलने के तीन घंटे के अंदर ही इसे जिला घोषित कर दिया। सीएम की घोषणा के बाद खैरागढ़ छुईखदान गंडई नया जिला बना। ये जिला राजनांदगांव से अलग हुआ है। इस जिले में एक ही विधानसभा सीट खैरागढ़ है। यहां से यशोदा वर्मा विधायक हैं। इस पूरे क्षेत्र में लोधी समाज की बहुलता है। खैरागढ़ विधानसभा सीट से विक्रांत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे हैं। पिछले तीन चुनावों से विक्रांत सिंह टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया गया है। युवा वर्ग को साधने के लिए इस बार जातिगत समीकरण को छोड़कर भाजपा ने विक्रम सिंह को प्रत्याशी बनाया है।

विक्रांत सिंह खैरागढ़ के बाजार अतरिया क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य व जिला पंचायत राजनांदगांव के उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के कई पदों पर रह चुके हैं।खैरागढ़ महाविद्यालय में 2001-2002 में हुए चुनाव से राजनीति की शुरुआत करने वाले विक्रांत सिंह 2 बार नगर पंचायत खैरागढ़ के अध्यक्ष रहे। जनपद पंचायत खैरागढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विक्रांत सिंह के पास भाजयुमो संगठन में काम करने का भी अनुभव है। वे भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं। विक्रांत सिंह पिछले 15 सालों से पूरे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं।

वर्तमान विधायक- खैरागढ़ से यशोदा वर्मा विधायक हैं। साल 2022 में यशोदा वर्मा ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। यशोदा राजनांदगांव जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा वह जनपद पंचायत सदस्य और अपने गांव में भी सरपंच रह चुकी हैं।चुनाव में यशोदा वर्मा ने भाजपा के कोमल जंघेल को 20 हजार से भी अधिक वोटों से हराया था।

काफी समय से खैरागढ़ वासी इसे जिला बनाने की मांग कर रहे थे। ये पहले राजनांदगांव के अंतर्गत पड़ता था। हालांकि साल 2022 में हुए उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने जीत प्रमाण पत्र मिलने के तीन घंटे के अंदर ही इसे जिला घोषित कर दिया।सीएम की घोषणा के बाद खैरागढ़ छुईखदान गंडई नया जिला बना। ये जिला राजनांदगांव से अलग हुआ है। इस जिले में एक ही विधानसभा सीट खैरागढ़ है। यहां से यशोदा वर्मा विधायक हैं। इस पूरे क्षेत्र में लोधी समाज की बहुलता है।

इस सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 2,01,411 है। यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,874 है। जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 99,537 है। यहां पुरुष मतदाता महिला मतदाता के मुकाबले अधिक हैं।

प्रमुख मुद्दे -इस क्षेत्र में रोजगार, सड़क, बिजली की समस्या मुख्य चुनावी मुद्दा है। जिला बनने के बाद यहां के लोगों की कई मांगें लंबित है। यहां सड़क और गंदे नाली की समस्या प्रमुख मुद्दा है। यहां का वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा, गंडई भी विकास की बाट जोह रहा है। इस सीट पर युवाओं का रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। इस इलाके का कई क्षेत्र जिला बनने के बाद भी विकसित नहीं हुआ है। रोजगार न होने से युवा परेशान हैं। इस बार क्षेत्र के लोग बड़े उद्योग और रोजगार की मांग को लेकर वोट करेंगे।

साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर देवव्रत सिंह ने जेसीसीजे से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। देवव्रत सिंह ने भाजपा के कोमल जंघेल को हराकर यह विधानसभा सीट जेसीसीजे की झोली में डाल दिया। हालांकि देवव्रत सिंह की अचानक मौत हो गई। इसके बाद साल 2022 में यहां उपचुनाव हुए। 2022 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को 87879 वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 52.97 था। वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को 67703 वोट मिले थे। भाजपा का वोट प्रतिशत 40.81 था।

विनिंग फैक्टर- खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी लोधी समाज की है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वनांचल में आता है। इस सीट पर लोधी समाज निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में साहू और ओबीसी समाज के वोटर भी हैं।

भाजपा के नहले पर कांग्रेस का दहला

भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर जारी करने का फैसला लिया, उसके एक दिन पहले ही कांग्रेस ने रायपुर में मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल को लेकर आरोप पत्र जारी कर दिया। महीनों से तैयारी करने के बाद भी भाजपा पीछे रह गई। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो सितंबर को रायपुर में जारी किया। खबर है कि आरोप पत्र के बहाने अमित शाह ने भ्रष्टाचार का लेप लगाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखे तीर छोड़े। 2003 के विधानसभा चुनाव के पहले भी भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया अजीत जोगी के फोटो के साथ आरोप पत्र जारी किया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के फोटो के साथ आरोप पत्र जारी किया है।आरोप पत्र में आईएएस-आईपीएस और कई विषयों का उल्लेख है,पर कभी भाजपा नेताओं के साथ गलबहिये डालने वाले कोल स्कैम के एक आरोपी का आरोप पत्र में नाम न होना चर्चा का विषय है।

उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के तीर

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पिछले दिनों सरगुजा इलाके में बातों ही बातों में ही तीर चला दी। टीएस सिंहदेव ने ये तीर अपने दुश्मनों पर चलाई, जिन लोगों ने उनके बुरे दिनों में कांटे बोने का काम किया था। टीएस सिंहदेव ने निशाना साधते किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि लक्ष्य में तो विधायक वृहस्पत सिंह थे। यह तो सभी जानते हैं कि सरगुजा इलाके में टीएस सिंहदेव की अच्छी पकड़ है और उनके सहयोग तथा समर्थन के बिना कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता। माना जा रहा है कि वृहस्पत सिंह ने सिंहदेव को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाया था। इसके चलते टीएस सिंहदेव को राजनीतिक नुकसान भी हुआ। सिंहदेव साहब तभी से वृहस्पत सिंह से नाराज चल रहे हैं। खबर है कि टीएस सिंहदेव रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से अजय तिर्की को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। सिंहदेव के समर्थक अजय तिर्की को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब देखते हैं टीएस सिंहदेव भारी पड़ते हैं या वृहस्पत सिंह।

कही-सुनी

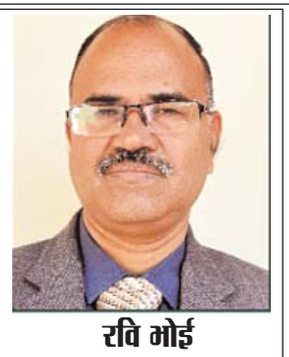

रवि भोई

क्या अमित जोगी पाटन से चुनाव लड़ेंगे

चर्चा है कि जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी इस बार पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। कहते हैं अमित जोगी ने पिछले दिनों पाटन विधानसभा में सभा ली और अपने कार्यकर्ताओं से भेंट-मुलाक़ात की। भाजपा ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है। वे यहाँ से अभी विधायक हैं। माना जा रहा है कि पाटन सीट से अमित जोगी के चुनाव लड़ने से मुकाबला रोचक हो जाएगा। वैसे अमित मरवाही सीट से एक बार विधायक रह चुके हैं। जाति प्रमाणपत्र के चक्कर में वे पिछली बार मरवाही उपचुनाव नहीं लड़ पाए। जाति प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद उनको नई सीट तलाशनी ही पड़ेगी। इस कारण शायद वे राजनीतिक लाभ के लिए पाटन की ओर रुख करने के मूड में हैं।

भाजपा बदल सकती है दो प्रत्याशी

कहते हैं भाजपा अब तक घोषित 21 प्रत्याशियों में से दो प्रत्याशी को बदल सकती है। चर्चा है कि संघ के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में दो प्रत्याशियों को लेकर भारी असंतोष सामने आया है। किन दो प्रत्याशियों को बदले जाने का मन बनाया गया है , इसका खुलासा अभी कोई नहीं कर रहा है। वैसे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा के भीतर मुखालफत की आग सुलगने लगी है। सराईपाली विधानसभा में तो बगावत ही हो गया। यहां से 2018 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रहे श्याम तांडी दल-बल के साथ कांग्रेस में चले गए। यहां गांडा समाज भी प्रत्याशी चयन को लेकर मुखर हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है।

अब नहीं बनेगी भाजपा की चुनाव अभियान समिति

कहते हैं कि चुनाव अभियान समिति के प्रमुख को लेकर विवाद की स्थिति बनने के कारण अब भाजपा हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में इस समिति को नहीं बनाने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस समिति का मुखिया विधायक बृजमोहन अग्रवाल को बनाना चाहते थे। उन्होंने इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा था, लेकिन डॉ रमन सिंह इस समिति की कमान धरमलाल कौशिक को दिए जाने के पक्ष में थे। खबर है कि विवाद के कारण जेपी नड्डा ने समिति गठन का प्रस्ताव टाल दिया है।

अब ईडी के निशाने पर आईपीएस

कहते हैं ईडी के निशाने पर अब राज्य के कुछ आईपीएस अफसर निशाने पर आ गए हैं। कोल लेवी के मामले में भी कुछ पुलिस अधिकारी ईडी के टारगेट में आए थे, लेकिन ईडी ने तब उन पर शिकंजा नहीं कसा था। ईडी की काली सूची में आए पुलिस अफसरों को राज्य सरकार ने ही किनारे लगा दिया। इस कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया। कोल लेवी मामले में ईडी आईएएस और माइनिंग अफसरों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही। कहा जा रहा है महादेव एप के बहाने ईडी पुलिस अफसरों को निशाने पर ले सकती है। पुलिस अफसरों के नामों को लेकर राज्य में अफवाहों का बाजार गर्म है।

बैज के खास महासचिव बने गेंदू

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने करीबी मलकीतसिंह गेंदू को अंतत: महासचिव संगठन और प्रशासन का जिम्मा सौंप दिया। इसकी चर्चा दीपक बैज के पीसीसी चीफ बनने के बाद से ही थी। प्रदेश कांग्रेस में अपने करीबी को महासचिव संगठन और प्रशासन बनाने की परंपरा मोतीलाल वोरा ने शुरू की। मोतीलाल वोरा ने अपने विश्वस्त सुभाष शर्मा को यह जिम्मेदारी दी थी। चरणदास महंत ने अपने किसी करीबी को महासचिव संगठन और प्रशासन बनाने की जगह सुभाष शर्मा को ही चलाते रहे। वैसे धनेन्द्र साहू के जमाने में भी फेरबदल नहीं हुआ था। जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने सुभाष शर्मा की जगह गिरीश देवांगन को महासचिव संगठन और प्रशासन बना दिया। मोहन मरकाम के कार्यकाल में पहले रवि घोष ने यह जिम्मेदारी संभाली। कुछ काम अमरजीत चावला को मिला। इस पर बाद में विवाद भी हुआ। मोतीलाल वोरा द्वारा शुरू की गई परंपरा को दीपक बैज ने आगे बढ़ाया।

छग भाजपा की मौजूदा हालात से संघ खफा

कहते हैं कि पिछले दिनों सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के नेतृत्व में रायपुर में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत को लेकर संघ के नेता आश्वस्त नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि संघ के नेताओं ने राज्य में भाजपा की स्थिति को कांग्रेस के मुकाबले कमजोर पाया। खबर है कि अब संघ के नेता जिलों में भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और 2023 में राज्य में भाजपा की सरकार बनवाने में पूरी ताकत लगाएंगे।

ईडी के बड़े एक्शन की चर्चा

चर्चा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में ईडी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा एक्शन कर सकती है। राज्य में ईडी कोल स्कैम, शराब और माइनिंग के अलावा चावल वितरण में गड़बड़ी, डीएमएफ की राशि आबंटन में गड़बड़ी, जल जीवन मिशन और महादेव एप के जरिये ऑनलाइन सट्टा की जाँच कर रही है। कोल स्कैम, शराब और महादेव एप में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब देखते हैं ईडी का अगला एक्शन क्या होता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

कबीर चबूतरा में पांच दिवसीय रचना शिविर का अभिनव आयोजन

रायपुर। श्रीकांत वर्मा पीठ (छ. ग.), छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और जिला प्रशासन-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के संयुक्त तत्वाधान में कबीर चबूतरा में 24 अगस्त से 28 अगस्त तक पांच दिवसीय रचना शिविर का अभिनव आयोजन किया गया. इस रचना शिविर में देश के ख्यातिनाम कथाकारों, आलोचकों, कवियों और उपन्यासकारों की रचनात्मक सहभागिता रही. 5 दिन और 20 सत्रों में बंटा ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा और प्रयोगधर्मी था, जिसकी जरूरत हिंदी के परिदृश्य में बहुत समय से अनुभव की जा रही थी. रचना शिविर में गगन गिल (दिल्ली) जयशंकर (नागपुर) मधु बी जोशी (गाज़ियाबाद) राजुला शाह (भोपाल) सत्यनारायण (जोधपुर) हरि नारायण (दिल्ली) अच्युतानंद मिश्र (कोच्चि) आनंद हरषुल (रायपुर) योगेंद्र आहूजा (दिल्ली) आशुतोष दुबे (इंदौर) अंबर पांडे (इंदौर) रश्मि रावत (दिल्ली) राहुल सिंह (देवघर) प्रत्यक्षा(दिल्ली) अविनाश मिश्र (दिल्ली) प्रिया वर्मा (लखनऊ) प्रियंका दुबे(इंदौर) जया जादवानी (रायपुर) प्राची साहू (राजनांदगांव) महिमा कुशवाहा (अंबिकापुर) हर्ष तिवारी (अंबिकापुर)श्री कुमार(बिलासपुर) मुदित मिश्र (बिलासपुर) सुमित शर्मा(बिलासपुर) स्मिता (जशपुर)ने अपनी रचनात्मक सहभागिता दी. पहले दिन 24 अगस्त को शुभारंभ सत्र के बाद पहला सत्र सृजन, समाज और साहित्य, दूसरा सत्र उपन्यासपाठ और तीसरा सत्र वैश्विक भूमिका पर वक्तव्य हुए।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दावा-आपत्ति 11 तक

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में अभी चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने तथा संशोधन के लिए 11 सितम्बर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान आगामी शनिवार, 2 सितम्बर और रविवार, 3 सितम्बर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में इसके लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे सुदृढ़ लोकतंत्र एवं मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं तथा अपने मताधिकार का उपयोग करें। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य में फेटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पूर्व में 2 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित की थी। आयोग ने इसके लिए अंतिम तिथि अब 11 सितम्बर 2023 तक बढ़ा दी है। आयोग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस बारे में लिखित में संसूचित भी किया गया है। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए सभी मतदान केन्द्रों में आगामी शनिवार, 2 सितम्बर तथा रविवार, 3 सितम्बर को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आरडीए में ऑनलाईन भुगतान प्रारंभ

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण ने आवंटितियों को अपनी संपत्तियों की राशि भुगतान करने के लिए ऑनलाईन पेमेन्ट की सुविधा प्रारंभ कर दी है। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू के अनुसार भुगतान करने हेतु आवंटितियों को प्राधिकरण से उनके मोबाईल पर एसएमएस से डिमान्ड नंबर मिलेगा। इसके बाद भुगतान के लिए आवंटितियों को प्राधिकरण की वेबसाईट आरडीए डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर जाना होगा।

वेबसाईट में ऊपर दाहिनी ओर अंग्रेजी में ऑनलाईन पेमेन्ट का मेन्यू दिखेगा। इसमें क्लिक करने पर ऑनलाईन भुगतान हेतु ई-लिंक में स्थानांतरित किया जाएगा। जिसमें ऑनलाईन विंडो खुल जाएगी। इसमें डिमान्ड नंबर डालते ही आवंटिति के भुगतान का विवरण उसकी संपत्ति के विवरण के साथ आ जाएगा। भुगतान किन किन मदों में होगा इसका विवरण होगा। इसमें दर्शित कुल राशि का भुगतान हेतु नीचें दाहिनी ओर मेक ऑनलाईन पेमेन्ट का बटन क्लिक करना होगा। इससे बाद पेमेन्ट इन्फरमेशन विंडो खुलेगी। जिसमें भुगतान हेतु क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा यूपीआई के विकल्प उपलब्ध होगा। यूपीआई के अंतर्गत भीम यूपीआई, पे-फोन, जीपे (तेज), पेटीएम व व्हॉट्सएप्प के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। यूपीआई से भुगतान के लिए क्यू आर कोड से भुगतान हो सकेगा।

धर्म और जाति के आधार पर संवैधानिक अधिकारों का हो रहा हननः लखन सुबोध

रायपुर। कट्टर धार्मिक जातिवादी और पितृसत्तात्मक ताकतों द्वारा संस्कृति, धार्मिक परंपराओं एवं जातिगत मुद्दों के आधार पर प्रदेश में अनेक हिंसात्मक वारदात छत्तीसगढ़ में लंबे समय से जारी है। सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर मानसिक प्रताड़ना के लगभग 50 हजार से अधिक मामले में थाने में दर्ज होने के बावजूद भी राजनीतिक संरक्षण के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका में न्यायमूर्तियों द्वारा दिये गये निर्देशों को भी राज्य सरकार के आला अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। उक्त आरोप प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में पीपुल्स यूनियर फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के पदाधिकारी लखन सुबोध, डिग्री प्रसाद चौहान, अखिलेश एडगर, रिनचिन एवं आशीष बैक ने संयुक्त रूप से लगाया। पत्रकारवार्ता में वार्ताकारों में लखन सुबोध डिग्री प्रसाद चौहान एवं रिनचिन ने आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय से सामाजिक परंपराओं के नाम पर कुछ जाति समूहों एवं समुदाय विशेष द्वारा अनेक लोगों को पीड़ित कर मानव अधिकार संवैधानिक हनन की जानकारी दी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ क्रिश्चयन फोरम एवं पीयूसीएल द्वारा संवोंच्च न्यायालय में भी पत्र लिखकर अंतरजातीय विवाह अपनी मर्जी से धर्मांतरण एवं अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार के उपेक्षित रवैये की जानकारी दी है। पत्रकारवार्ता में थर्ड जेंडर समूह द्वारा भी लंबे समय से अपने समुदाय की उपेक्षा की जानकारी दी गई।

इंदिरा बैंक खातेदारों की डूबी रकम वापसी के आसारः कन्हैया

रायपुर। इंदिरा बैंक घोटाले की जांच में लगातार आई तेजी और घोटालेबाजों से मात्र एक महीने में ढाई करोड रुपए की वसूली किए जाने का स्वागत करते हुए इंदिरा बैंक संघर्ष समिति के अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ,शैलेश श्रीवास्तव ,शंकर सोनकर, श्रीमती नूरजहां और सुरेश बाफना ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए पत्र लिखकर इंदिरा बैंक के खातेदारों को उनकी डूबी हुई जमा राशि वापस कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमाकर्ताओं को राशि वापस दिलाई है इस तरह इंदिरा बैंक के खातेदारों को भी उनकी जमा राशि वापस दिलाने के लिए आदेश जारी करने की कृपा करेंगे। अग्रवाल ने कहा कि 2006 में घोटाले का शिकार हुई इंदिरा बैंक को डूबाने वालों से राशि वसूली की प्रक्रिया 12 वर्षों तक भाजपा की सरकार ने नहीं की थी, सरकार में बैठे लोग घोटालेबाजों को बचाने में लगे रहे इसलिए 12 वर्षों में एक रुपए भी राशि वसूल नहीं की जा सकी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी वसूली की कार्रवाई के बाद खातेदारों में रकम वापसी की उम्मीद बढ़ी है ,हम सभी निवेदन करते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व खातेदारों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश जारी होंगे।चुनाव पूर्व खातेदारों को रकम वापसी उनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा।

जो वायदे किये, वो पूरे किये, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया बहुत अच्छा कामः राहुल

सांसद राहुल गांधी ने राजीव युवा मितान सम्मेलन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा

- प्रदेश में शासकीय नियुक्तियों में स्टाइपेंड व्यवस्था समाप्त
- कौशल विकास से बढ़े रोजगार, छत्तीसगढ़ में हो रहा बढ़िया काम
- पूरे देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में
- जब भी हमें अवसर मिला लोगों को ताकत देने का काम किया- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
- राजीव युवा मितान सम्मेलन में दो लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया

रायपुर। मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित वायदे से ज्यादा काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

दो लाख से अधिक युवाओं की अभूतपूर्व उपस्थिति में हुए इस सम्मेलन में श्री राहुल गांधी ने कहा हमने यहाँ रोजगार सृजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। मैंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी से कहा कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल हैं। हर जिले में आप कुछ अलग सा बनाते हो। छोटे उद्यमियों को बैंक लिंकेज मिलना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आपका फोकस इन पर होना चाहिए, इसकी मार्केटिंग हो, मुझे खुशी है कि बघेल जी ने इस पर अच्छा काम किया है। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुला है। छत्तीसगढ़ देश का केंद्र है। आपको देश का लाजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लाजिस्टिक सेंटर बन पाये। आप दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िये। इससे छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट केवल भारत ही नहीं, दुनिया में भी जाएं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के विकास के लिए युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए ही हमने राजीव युवा मितान क्लब बनाये हैं। हर क्लब को एक लाख रूपए मिल रहे हैं। तीन लाख युवाओं को हमने क्लब में जोड़ा है। हमने पेसा कानून के माध्यम से आदिवासियों को उनके हक दिलाए। आदिवासी का मतलब इस देश की धरती के सबसे पहले आप मालिक हैं। मतलब जमीन पर जंगल पर जल पर आपका हक पहला बनता है।

श्री राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के डीएनए में प्यार है मोहब्बत है। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर मोहब्बत के साथ इज्जत के साथ रहना है। यह सबसे पुराना मैसेज है जिसे हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिया। नफरत से और हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता। हिंसा से देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। जब सबको एक साथ लाया जाता है तो देश जुड़ता है। छत्तीसगढ़ का भविष्य आपका है। आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि पांच साल पहले जब राहुल गांधी जी आये थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आम आदमी को लाभ हो, आदिवासियों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। हमने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों को लाभ हुआ। किसानों को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस नहीं लेते। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा हमारे साथ है। युवा राष्ट्र की संपत्ति है और इस ऊर्जा का सही उपयोग हमें करना है। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। हम लोगों को अधिकार संपन्न बनाते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जब तक हमें अवसर मिला, लोगों को ताकत देने का काम किया है। पहली बार युवाओं का ऐसा मेला छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव युवा मितान क्लब को हर साल एक लाख रुपए दिया जा रहा है ताकि हमारे युवा साथी अपने गाँव की संस्कृति, खेलकूद और शासन की जानकारी भी वंचित वर्गों तक पहुँच पाए। ये दिन रात मेहनत करते हैं इन सब तक ये शासन की योजनाओं की जानकारी देते हैं। आने वाले पाँच सालों में हमने दस से बारह लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने अपना अमूल्य समय देने के लिए श्री राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, सांसद श्री दीपक बैज, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने स्वागत भाषण किया।

छत्तीसगढ़ के युवा राहुल गांधी के साथ खड़े हैं-दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने राजीव युवा मितान सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ की धरती पर हमारासौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे देश के नेता राहुल गांधी उपस्थित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर यात्रा देश के बदलाव के लिए, देश के परिवर्तन के लिए और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पैदल यात्रा की। देश को शांति का संदेश दिया। आज देश बंटवारे की ओर है। उसे राहुल गांधी जी ने शांति का संदेश दिया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह युवा सम्मेलन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो जनता की योजनाओं के बीच जाते हैं, जनता को सरकार की योजना की जानकारी देना, लागू करवाना है। युवा मितान जनता की मदद में लगे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पौने 5 साल में कांग्रेस सरकार में बहुत काम हुआ है और आपके निर्देशन में कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर योजना हर वर्ग तक पहुंचाई है। किसानों का कर्ज माफकिया है। 2500 धान की कीमत दी है। उन्होंने राहुल गांधी से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने जो वादे किए थे, एक-एक वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता2500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार माता बहनों को समर्थ बना रही है। मैं बस्तर से आता हूं। बस्तर में 15 साल की सरकार में नक्सलियों के नाम से आदिवासियों को गोली मारी जाती थी। आज एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होता। नक्सली पीछे चले गए हैं। बस्तर शांति की राह पर लौट चुका है। आपने हम जैसे युवाओं पर भरोसा किया है। आज युवा आपको देखने आए हैं आपके संदेश को सुनने आए हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.